।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

●वर्ष–5
●अंक–162
रायपुर, शुक्रवार
20 फरवरी 2026
●पृष्ठ–8
●मूल्य–3 रु.

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› कांग्रेस ने गरीबों की छत ...

प्रधानमंत्री ने ग्लोबल एआई समिट में दिया मानव मंत्र

एआई में बड़े बदलाव की ताकत, इस पर नियंत्रण जरूरी : मोदी

नई दिल्ली। एआई इम्पैक्ट लीडरशिप सम्मेलन 2026 के औपचारिक उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम बातें बताईं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक को लेकर शुरू में संदेह होता है, लेकिन ये नई पीढ़ी अब जिस तरह से एआई का इस्तेमाल कर रही है, वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई ने मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा दिया है, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एआई तकनीक को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने कहा भारत नई तकनीक बनाता है और साथ ही तेजी से नई तकनीक को अपनाता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत दुनिया के सबसे बड़े टेक पूल का केंद्र है। यह वैश्विक दक्षिण के लिए गर्व की बात है कि एआई सम्मेलन भारत में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, एआई मशीनों को बुद्धिमान बना रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रहा है। इस बार सबसे बड़ा अंतर ये है कि इस बार गति अभूतपूर्व है और इसका स्तर भी बहुत विस्तृत है। पहले तकनीक का असर दशकों में जाकर दिखता है। आज मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन की यात्रा पहले के मुकाबले बहुत तेज है।

प्रधानमंत्री ने एआई को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा, जिस तेजी से युवा वर्ग एआई को अपना रहा है, वह बेहद सराहनीय है। युवाओं में एआई सम्मेलन को लेकर गजब का उत्साह है। हमें अपना विजन बड़ा करने की जरूरत है और साथ ही ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। मौजूदा पीढ़ी के साथ हमें इस बात की भी चिंता है कि एआई को किस रूप में हम आने वाली पीढ़ी को सौंपेंगे। असल सवाल ये नहीं है कि हम एआई से भविष्य में क्या कर सकते हैं बल्कि ये है कि हम वर्तमान में एआई से क्या करें? ऐसे सवाल मानवता के सामने पहले भी आए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण परमाणु ऊर्जा है। हमने इसकी तबाही को देखा और साथ ही इसके सकारात्मक योगदान को भी देखा।

प्रधानमंत्री ने दुनिया को आगाह करते हुए कहा, एआई में बदलाव की ताकत है, लेकिन अगर ये ताकत दिशाहीन रही तो यह तबाही भी ला सकती है। एआई को मशीन केंद्रित से मानव केंद्रित बनाना, इसे संवेदनशील बनाना, ये इस वैश्विक एआई सम्मेलन का आधारभूत उद्देश्य है। इस सम्मेलन की थीम, भारत का एआई को लेकर परिपेक्ष्य दर्शाती है, जो है सभी का कल्याण, सभी की खुशी।

प्रधानमंत्री ने कहा, एआई के लिए अभी इंसान सिर्फ डाटा पॉइंट हैं लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम एआई के लिए सिर्फ कच्चा माल बनकर न रह जाएं। इसलिए एआई का लोकतांत्रिकरण जरूरी है। यह इंसानों को सशक्त बनाने का माध्यम होना चाहिए। हमें एआई को खुली छूट देनी चाहिए, लेकिन साथ ही नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहिए। आज हम एआई को जिस दिशा में ले जाएंगे, वो ही हमारा भविष्य तय करेगी।

प्रधानमंत्री ने तकनीक में विश्वास की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज वैश्विक मानकों की स्थापना बेहद जरूरी है। डीपफेक और मनगढ़ंत कंटेंट समाज को अस्थिर कर रहा है। ऐसे में डिजिटल कंटेट पर प्रामाणिकता का लेबल होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या असली है और क्या एआई जनित। जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे ही वाटरमार्किंग और वैश्विक मानकों की जरूरत बढ़ती जा रही है। यह जरूरी है कि इस तकनीक में शुरू से ही विश्वास बनाकर रखा जाए। प्रधानमंत्री ने एआई को लेकर मानवीय विजन पेश करते हुए मानव का अर्थ बताया कि एम का अर्थ है नैतिक और नीतिपरक प्रणालियां (Moral and Ethical Systems), ए का मतलब जवाबदेह शासन (Accountable Governance), एन का मतलब राष्ट्रीय संप्रभुता (National Sovereignty), ए का अर्थ सुलभ और समावेशी (Accessible and Inclusive), और वी का मतलब वैध और विश्वसनीय (Valid and Legitimate)। भारत का यह मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा भारत, एआई में उज्जवल भविष्य देखता है।

भारत के डिजिटल सिस्टम के मुरीद हुए मैक्रों कहा- दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा मॉडल

नई दिल्ली। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने संबोधन की शुरुआत – नमस्ते शब्द के साथ की। इस दौरान उन्होंने कहा– इस शानदार शहर में, इस शानदार देश में हमारा स्वागत करने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा होस्ट किए गए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अपने संबोधन में भारत की तारीफ करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा, दस साल पहले मुंबई में एक सड़क विक्रेता बैंक खाता नहीं खोल सकता था। न पता, न कागजात, न ही पहुंच। और आज वही विक्रेता अपने फोन पर भुगतान स्वीकार करता है।फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस दौरान कहा कि भारत ने ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाया है, जो दुनिया में किसी और देश ने नहीं बनाया। उन्होंने बताया कि भारत ने 140 करोड़ लोगों के लिए डिजिटल पहचान (आईडी) बनाई है। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम हर महीने करीब 20 अरब लेन–देन करता है। इसके साथ ही भारत ने 50 करोड़ लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी भी जारी की है। मैक्रों ने कहा कि इन सबको मिलाकर एक व्यवस्था बनी है। यह एक खुला और जुड़ा हुआ डिजिटल सिस्टम है और यही इस सम्मेलन का मुख्य विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया अब डिजिटल क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने के नए दौर की शुरुआत पर खड़ी है। अपने मुख्य भाषण में मैक्रॉन ने संकेत दिया कि भारत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में ऐसे प्रतिबंध लागू हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर विचार कर रहे हैं। मैक्रों ने कहा कि महामहिम, आप भी इस क्लब में शामिल होंगे... बच्चों और किशोरों की सुरक्षा के लिए। बच्चों की सुरक्षा नियमन नहीं, बल्कि सभ्यता है। उन्होंने आगे कहा कि, पिछले साल जब फ्रांस और भारत ने पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह–मेजबानी की थी।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन साहस, धैर्य, रणनीति और आदर्श नेतृत्व का प्रेरक उदाहरण है, इसलिए हम सभी को अपने जीवन में शिवाजी जैसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में भी अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। अफजल खाँ के साथ हुई घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी ने संकट को भांपकर धैर्य और रणनीति से निर्णय लिया और विजय प्राप्त की।

मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम टिप्पणी, सबको फ्री सुविधाएं बांटना गलत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फ्रीबीज कल्चर (मुफ्त की रेवड़ियां) पर कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था।

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि देश के ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में हैं और फिर भी वे विकास को नजरअंदाज करते हुए मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं।

आपको लोगों के लिए रोजगार के रास्ते बनाने चाहिए,

ताकि वे कमा सकें और अपनी इज्जत और आत्म सम्मान बनाए रख सकें। जब उन्हें एक ही जगह से सबकुछ मुफ्त मिल जाएगा तो लोग काम क्यों करेंगे। क्या हम ऐसा ही देश बनाना चाहते हैं?

अचानक चुनाव के आस-पास स्कीम क्यों अनाउंस की जाती हैं? अब समय आ गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां, नेता फिर से सोचें। अगर हम इस तरह से उदारता दिखाते रहे तो हम देश के डेवलपमेंट में रुकावट डालेंगे। एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा ?हम भारत में कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं? यह समझ में आता है कि कल्याणकारी योजना के तहत आप उन लोगों को राहत दें, जो बिजली का बिल नहीं चुका सकते। जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं और जो नहीं हैं, उनके बीच कोई फर्क किए बिना मुफ्त सुविधा देना क्या तुष्टीकरण की नीति नहीं है ?सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कंपनी ने 2024 के विद्युत संशोधन नियमों के नियम 23 को चुनौती दी है। इसमें उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव है।राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो–महीने में लगभग 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है, बिना किसी शर्त के यानी उपभोक्ता चाहे कितना भी खर्च करे, पहली 100 यूनिट के लिए बिल नहीं देना होता।

प्रमुख समाचार

देशभक्ति दिल से होती है कानून से मजबूर ना करे: थरूर

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर ने 'वंदे मातरम' को लेकर चल रही बहस पर साफ कहा कि किसी भी नागरिक को गाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस की आलोचना कर कहा कि देशभक्ति दिल से होती है, और कानून बनाकर इस गाने को जबरन किसी की जुबान पर नहीं लाया जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश दिए हैं कि राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' अब सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में पूरा गाना अनिवार्य होगा। कांग्रेस नेता थरूर ने इस दौरान 'वंदे मातरम' के इतिहास का उल्लेख किया। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों और सत्याग्रहियों को प्रेरित करता था। उन्होंने कहा कि आज एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में राज्य और व्यक्तिगत अंतरात्मा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 'वंदे मातरम' गाती थी, लेकिन देश की धार्मिक विविधता को देखकर 'जन गण मन' को राष्ट्रगान चुना गया। संविधान सभा ने 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गीत का समान दर्जा दिया।

2027 में जिनेवा में होगा एआई समिट : गाइ पार्मेलिन

नई दिल्ली। स्विस राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन ने गुरुवार को घोषणा की कि स्विट्जरलैंड वर्ष 2027 में जिनेवा में एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि इससे डिजिटल नीति के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड की स्थिति मजबूत होगी और नियम–आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि होगी। भारत मंडपम में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन के दौरान स्विस पवेलियन में मीडिया से बातचीत करते हुए पार्मेलिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक को बेहतरीन बताया। दोनों नेताओं ने शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय वार्ता भी की। स्विस राष्ट्रपति ने कहा कि एआई केवल गति या अनुप्रयोग का विषय नहीं है, बल्कि इसका लोगों के जीवन पर सीधा और असाधारण प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच %एक्स% पर भी कहा कि जिनेवा में 2027 का समिट जिम्मेदार एआई उपयोग, वैश्विक संवाद, शासन और नियमन को आगे बढ़ाने में योगदान देगा।एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा, %नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एआई अभूतपूर्व गति से हमारे भविष्य को आकार दे रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सरकारें मिलकर काम करें, ज्ञान का आदान–प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें।

कांग्रेस फरवरी अंत तक जारी करेगी उम्मीद्वारों की पहली सूची

नईदिल्ली। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनावों के लिए आंतरिक समयसीमा तय कर ली है। मार्च–अप्रैल में चुनाव होने की उम्मीद है, और पार्टी की राज्य इकाई का कहना है कि उम्मीदवारों की पहली सूची फरवरी के अंत तक जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद मार्च की शुरुआत तक लगभग 80 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने समयसीमा का ब्यौरा दिया। उनकी यह घोषणा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के संभावित उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए राज्य के दो दिवसीय दौरे से ठीक पहले आई है। गोगोई ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्क्रीनिंग प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना है। केंद्रीय नेतृत्व ने हमें निर्देश दिया है कि पहली सूची इस महीने के अंत तक जारी कर दी जाए। उन्होंने आगे बताया कि मार्च के पहले सप्ताह तक लगभग 80 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे और घोषित कर दिए जाएंगे, जिनमें पहली सूची में शामिल उम्मीदवार भी होंगे।

डीआरडीओ- इसरो ने ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण

नईदिल्ली। भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम ने गगनयान कार्यक्रम के लिए ड्रोग पैराशूट के सफल क्वालिफिकेशन लेवल लोड परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह परीक्षण चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (टीबीआरएल) में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज (आरटीआरएस) सुविधा में किया गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, आरटीआरएस एक विशेष गतिशील परीक्षण सुविधा है जिसका उपयोग उच्च गति वाले वायुगतिकीय और बैलिस्टिक मूल्यांकन के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। यह परीक्षण 18 फरवरी, 2026 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), इसरो, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (एडीआरडीई), डीआरडीओ और टीबीआरएल की विभिन्न समर्पित टीमों के सहयोग से किया गया। आरटीआरएस गतिशील परीक्षण, जो क्वालिफिकेशन लेवल लोड का अनुकरण करता है।

भारत वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है : सुंदर पिचाई

नई दिल्ली,। राजधानी में आयोजितएआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और वैश्विक उद्योग जगत के दिग्गजों की मौजूदगी ने भारत की तकनीकी नेतृत्व क्षमता को नई पहचान दी। समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मुनल मेक्रोन , ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डिसिल्वा सहित अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहां सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार बदलाव की रफ्तार चौंका देती है।

सीईओ गूगल और अल्फाबेट सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार बदलाव की रफ्तार चौंका देती है। उन्होंने छात्र जीवन की यादें साझा करते हुए चेन्नई से आईआईटी खड़गपुर तक कोरोमंडल एक्सप्रेस की यात्रा का जिक्र किया और विशाखापत्तनम को कभी शांत तटीय शहर बताया। आज उसी शहर में गूगल 15 बिलियन डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के तहत फुल–स्टैक एआई हब विकसित कर रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने संबोधन में भारत के डिजिटल परिवर्तन की सराहना की।

फ्रांस से मजबूत रक्षा संबंध का भारत को लाभ मिलेगा

शशांक

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की तीन दिवसीय भारत यात्रा के दौरान मुंबई में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट हुई। दोनों नेता जिस गर्मजोशी से मिले, उससे दोनों देशों के रिश्तों की गहराई पता चली। इस दौरान मैक्रों ने दोनों देशों के संबंधों को 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा दिया। मैक्रों की इस यात्रा के दौरान भारत–फ्रांस के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज समेत 20 से अधिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। हालांकि इस दौरान रक्षा क्षेत्र में हुए समझौते, जिनमें हैमर मिसाइलों के भारत में उत्पादन और इसके लिए भारतीय कंपनी बीइएल और फ्रांस की कंपनी सैफरान के बीच हुआ समझौता, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मैक्रों का यह भारत दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमने यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किया है, जो काफी विस्तारित समझौता है। इस समझौते में फ्रांस की बड़ी भूमिका रही है और उम्मीद है कि हमें आगे भी फ्रांस की मदद मिलती रहेगी। इस समय दुनिया जिस बहुपक्षीय, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, साथ ही, दुनिया को व्यापार और आर्थिक जगत में जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे समय में भारत–फ्रांस दोस्ती बहुत आवश्यक है। दोनों देशों के बीच के रिश्ते इसलिए भी गहरे हो रहे हैं, क्योंकि दोनों देश लोकतांत्रिक हैं, सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों एक–दूसरे के लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हैं और उसे महत्व भी देते हैं। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साझा कदम उठाने की बात भी कही है, जो दुनियाभर में बढ़ते आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है।

मैक्रों भारत में चल रहे एआइ समिट में शामिल होने आये हैं, इससे पहले फ्रांस में हुए समिट में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां जा चुके हैं। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस में भी फ्रांस भारत का पार्टनर है। भारत चाहता है कि एआइ के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर उसकी एक पहचान बने, ताकि हमारे युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले। यह भी सच है कि आज की वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हमारे युवा भारत में ही काम करना चाह रहे हैं। ऐसे में, एआइ में आगे बढ़ने से युवाओं को भारत में ही अच्छा मौका मिलेगा। इसके साथ ही, भारतीयों की क्षमता से भी दुनिया वाकिफ है और कई देश हमारे युवाओं को अपने यहां बुलाना चाहते हैं। ऐसे में, मुझे लगता है कि भारतीय युवाओं के लिए अमेरिका ने जो रास्ते बंद किये हैं, उसकी भरपाई उन्हें फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों में हो जायेगी। हां, युवाओं को दूसरी भाषाएं सीखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर मौके उन्हें मिलेंगे।

मैक्रों का यह दौरा दिखाता है कि वे चाहते हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते मजबूत हों, क्योंकि पहले से ही फ्रांस यूरोप में भारत का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। हालांकि इस समय मैक्रों की अपनी घरेलू लोकप्रियता कम है, परंतु यदि वह भारत को साथ लेकर चलते हैं, जो इस समय वैश्विक दक्षिण का नेता बनकर उभरा है, तो उन्हें न केवल घरेलू स्तर पर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि वैश्विक स्तर के भी कई मामलों में उन्हें अग्रणी भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है। इसे मैक्रों भी बखूबी समझ रहे हैं।

यहां राफेल समझौते का जिक्र भी जरूरी है। गौरतलब है कि 114 अतिरिक्त राफेल खरीदने का रास्ता भारत सरकार द्वारा लगभग साफ कर दिया गया है। अगले कुछ महीनों में राफेल सौदों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और वह भारत विरोधी कोशिश में भी लगा रहता है। ऐसे में, आतंकवाद पर नकेल कसने तथा अपने रक्षा क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम फ्रांस के साथ और राफेल खरीद के समझौते करें। यह भी सब जानते हैं कि पाकिस्तान की पीठ पर अमेरिका और चीन खड़े हैं।

हालांकि, रूस और ईरान के साथ भी हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन इन दोनों देशों पर दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे लिए नये मित्र बनाना भी आवश्यक है। मैक्रों के भारत दौरे के दौरान फ्रांस से न केवल 114 राफेल 4।5 वर्जन खरीदने की बात हुई है, बल्कि भारत ने यह भी कहा है कि वह 50 प्रतिशत राफेल का उत्पादन भारत में ही करना चाहता है। इसके लिए तकनीक स्थानांतरण पर भी बातचीत हुई है, ताकि हम उसे अपने देश में ही बना सकें।

ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट-2 के तहत सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी

मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को किया ढेर

बीजापुर। कर्रेगुट्टा क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन "ब्लैक फॉरेस्ट-2" के दौरान आज एक बड़ी मुठभेड़ में पांच नक्सली मारे गए है। यह कार्रवाई जिले में जारी नक्सल विरोधी अभियान, सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन के तहत की गई है।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। घटनास्थल से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को इस सफलता की सूचना दे दी गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन अभियान जारी रखा है। मुठभेड़ के दौरान और बरामदगी से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी प्रतीक्षित है। यह कार्रवाई क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे लगातार अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है और स्थानीय सुरक्षा बलों की तत्परता और तैयारियों को दर्शाती है।

महिला आरक्षक के साथ शारीरिक शोषण का आरोप, डिप्टी कलेक्टर निलंबित

बालोद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके को महिला आरक्षक द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है। मामला कुछ माह पहले बालोद जिले के डौंडी थाना में दर्ज हुआ था, जिसमें महिला आरक्षक ने दिलीप उइके पर शादी का झांसा देकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाने, जबरदस्ती गर्भपात करवाने और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया था।

महिला आरक्षक ने इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को आवेदन कर 12 बिंदुओं में शिकायत की है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि जिला प्रशासन बीजापुर द्वारा डिप्टी कलेक्टर को संरक्षण देते हुए फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए और नियम के विरुद्ध अवकाश स्वीकृत किए गए। शिकायत के साथ महिला ने सभी सह प्रमाणिक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। महिला आरक्षक ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2017 में वह डौंडी स्थित आईटीआई में

पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान दिलीप उइके से उनकी बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। दिलीप ने शादी का वादा किया और महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया।

महिला ने कहा कि मार्च 2017 में पहली बार गर्भवती होने पर जब उसने दिलीप को बताया, तो उन्होंने पढ़ाई पूरी करने और नौकरी पाने तक शादी को टालने का झांसा दिया। इसके बाद महिला से जबरदस्ती दवा देकर गर्भपात करवाया गया। अगस्त 2017 में महिला की पुलिस विभाग में नौकरी लग गई। महिला ने बताया कि अपने भविष्य में दिलीप के साथ शादी की आशा में उसने उसकी पढ़ाई, कोचिंग और अन्य खर्चों के लिए हर माह 4-5 हजार रुपये उसके खाते में ट्रांसफर किए।

पीएससी परीक्षा में सफल होने के बाद वर्ष 2020 में दिलीप डिप्टी कलेक्टर बने और बीजापुर में पोस्टिंग हुई। नौकरी लगने के बाद जब महिला ने शादी के लिए कड़ा रुख अपनाया, तो उसने महिला को झांसा दिया कि अभी नौकरी लगी है, अच्छे से सैटल हो जाऊं, फिर शादी करूंगा। इसके बावजूद बार-बार शारीरिक संबंध बनाए गए।

जनवरी 2025 महिला बीजापुर में डिप्टी कलेक्टर के सरकारी आवास में लगभग एक सप्ताह रही। इसी दौरान शादी से पहले गर्भवती होने की जानकारी देने पर दिलीप ने उसे जबरदस्ती गर्भपात की दवा दी।

फरवरी और मार्च 2025= बार-बार शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए। महिला ने बैंक से लोन लेकर कुल 3,30,000 रुपये दिलीप के खाते में ट्रांसफर किए।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि फरवरी 2023 में दिलीप ने उसके नाम पर मारुति कार (ष्टत्र 24ञ्ज3967) खरीदी। फरवरी 2024 में उसने महिला के खाते में राशि ट्रांसफर कर कार को अपने नाम कर लिया।

महिला की शिकायत पर डौंडी थाना में स्नद्धक्र दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजापुर प्रशासन ने डिप्टी कलेक्टर को निलंबित कर दिया है।

40 श्रमिकों का हुआ पंजीयन योजनाओं की दी गई जानकारी

कोण्डागांव। छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप एवं कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार जिला कोण्डागांव में निर्माण श्रमिकों एवं असंगठित कर्मकारों के पंजीयन, नवीनीकरण तथा विभागीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत बड़े बंजोड़ा में मोबाइल पंजीयन एवं नवीनीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला कोण्डागांव द्वारा किया गया। शिविर में कुल 40 श्रमिकों का पंजीयन संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। इनमें नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। अधिकारियों ने उपस्थित श्रमिकों से अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराकर शासन की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। शिविर के माध्यम से श्रमिकों में योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।

दुष्कर्मी आरोपी और उसके साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जशपुर। नाबालिग बालिका को प्रेमजाल में फंसाकर मिलने के बहाने बुलाकर उससे और उसकी सहेली से दुष्कर्म करने वाले कथित प्रेमी और उसके सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार, दोनों पीड़िताएं आपस में सहेली हैं। 17 वर्षीय बालिका ने लिखित आवेदन में बताया कि दिसंबर 2025 में उसका ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश उर्फ राहुल पैंकरा से मोबाइल के माध्यम से परिचय हुआ। आरोपी ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर शादी का प्रलोभन दिया। वहीं 14 फरवरी को आरोपी ने लड़की को लैलूंगा मिलने बुलाया। लड़की अपनी सहेली (16 वर्षीय) के साथ पत्थलगांव होते हुए बस से लैलूंगा पहुंची।

अटल चौक लैलूंगा पर आरोपी राहुल अपने दोस्त जयकिशन धोबा के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी

13एमयू 3456 से दोनों को लेने आया।

उसके बाद चारों ग्राम सोनाजोरी गए, जहां रात में आरोपी प्रकाश और उसके साथी चारों एक बाइक से सोनाजोरी जंगल गये। वहां मुख्य आरोपी ओमप्रकाश पैंकरा ने पहले उसकी कथित प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी सहेली के साथ भी दुष्कर्म किया तथा घटना किसी को बताने पर मारपीट की धमकी दी।

इसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी ओमप्रकाश पैंकरा से पूछताछ की। इस दौरान उसने दोनों युवतियों के साथ दुष्कर्म करना स्वीकार किया है, जबकि जयकिशन धोबा घटना में उसका सहयोगी पाया गया। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सीजी 13 एमयू 3456 जब्त की गई है। ओमप्रकाश पैंकरा उर्फ प्रकाश उर्फ राहुल पैंकरा पिता सुवर्धन पैंकरा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम किलकिला, थाना लैलूंगा (मुख्य आरोपी) जयकिशन धोबा पिता भगवती धोबा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम टुरटुरा, थाना लैलूंगा

आदिवासी आश्रम में छात्र की मौत से गुस्से में समाज

नेशनल हाइवे पर किया चक्काजाम, अधीक्षक पर कार्रवाई के साथ मुआवजे की कर रहे मांग

गरियाबंद। आदिवासी बालक आश्रम, बड़े गोबरा के छात्र राघव मंडावी के मौत से आक्रोशित आदिवासी समाज ने आज नेशनल हाइवे 130 ष्ट पर चक्काजाम कर दिया है, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। समाज के लोग आश्रम अधीक्षक पर कार्रवाई के साथ मृतक छात्र के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार।

ग्राम भाठीगढ़ में संचालित शासकीय आदिवासी बालक आश्रम में रहकर ग्राम गजकन्हार, विकासखण्ड नगरी निवासी छात्र राघव कुमार पढ़ाई कर रहा था। 20 जनवरी को छात्र ने आश्रम के साथियों और कर्मचारियों को तबीयत खराब होने की जानकारी देते हुए माता-पिता से बात कराने की गुहार लगाते रहा, लेकिन आश्रम के कर्मचारियों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया।

गणतंत्र दिवस के दिन छात्र के पिता फिरतु राम मंडावी अपने बच्चे को देखने आश्रम पहुंचा, तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपने बेटे राघव को बेहद कमजोर के साथ ही आश्रम के बिस्तर में सोया पाया। पिता के हाल-चाल पूछने पर उसने बताया पिछले कई दिनों से वह बीमार है, और अधीक्षक के साथ कर्मचारियों को घर में सूचना देने के लिए कई बार बोलने के बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। आदिवासी छात्रावास के बच्चे की इलाज में लापरवाही से मौत, इकलौती संतान खोने से सदमे में माता-पिता, आश्रम अधीक्षक पर लापरवाही का आरोप पिता ने तत्काल छुट्टी के लिए आवेदन देकर अपने बीमार बच्चे को इलाज के लिए 26 जनवरी के दोपहर अपने घर ले गया।

घर में इलाज कराने के बाद कोई सुधार नहीं होने पर धमतरी स्थित अस्पताल ले गया, जहां छात्र राघव मंडावी की शुक्रवार सुबह 4 बजे मौत हो गई। इकलौते बेटे को खोने से हताश पिता ने रो-रोकर बताया कि समय में यदि इलाज कराया जाता तो आज उसका बच्चा जिन्दा होता।

जनपद सदस्य सुकचंद धुव्र ने आरोप लगाया कि आश्रम अधीक्षक की लापरवाही के चलते राघव की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि राघव की तबीयत खराब होने पर स्वयं उसके परिवार के साथ इलाज कराने धमतरी ले गया था, लेकिन राघव की मौत हो गई। ध्रुव ने मामले की निष्पक्षता से जांच कराने के साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

धान उठाव की धीमी गति पर शासन सख्त, हटाए गए मार्कफेड डीएमओ किशोर चंद्रा

गरियाबंद। जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान का उठाव बेहद धीमी गति से होने पर शासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कुल 50.66 लाख क्विंटल धान में से अब तक केवल 29 लाख क्विंटल का ही उठाव हो सका है। खरीदी केंद्रों में तय बफर लिमिट से छह गुना ज्यादा धान जमा होने के कारण केंद्रों में जाम की स्थिति बनी हुई थी। धान उठाव में देरी और केंद्रों में जमा अधिक मात्रा को लेकर समिति ने बार-बार पत्राचार कर अधिकारियों को चेताया। इस कार्रवाई के बाद कलेक्टर की नाराजगी भरे पत्र के बाद 18 फरवरी की देर रात आदेश जारी कर मार्कफेड छ्वरूद्ग किशोर चंद्रा को पद से हटाकर कबीरधाम भेज दिया गया।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

नल कनेक्शन काटने पहुंचे निगम कर्मियों को मिली धमकी

जगदलपुर। बदलते समय में कोई भी काम सुरक्षित नहीं है। यहां तक नल कनेक्शन काटना भी आज के समय में खतरे से भरा हो गया है। ऐसा ही एक मामला जगदलपुर में सामने आया है, जहां नल कनेक्शन काटने पहुंचे निगम की टीम को बकायादार ने गोली से मारने की धमकी दे डाली। वीडियो में कैद यह पूरा वाकया सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शहर में बकायादारों से जलकर वसूली के लिए नगर निगम अभियान चला रहा है। इस कड़ी में निगम की टीम मोतीलाल नेहरू वार्ड में नल कनेक्शन काटने पहुंची थी। इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। इनमें से एक शख्स ने तो निगम कर्मियों को गोली मारने की धमकी तक दे डाली। बताया जा रहा है कि वार्ड में लंबे समय से जलकर बकाया है, जिस पर निगम सख्ती बरत रहा है। विरोध के दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस पूरे घटनाक्रम का एक कथित वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है निगम कर्मियों ने मामले को गंभीर बताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है।

अलग-अलग मामलों में छह गांजा तस्कर गिरफ्तार

महासमुंद। महासमुंद पुलिस ने नशीला पदार्थ, अवैध शराब और मादक पदार्थों पर नकेल कसने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के बाद से जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ सख्ती जारी है। ताजा मामले में तीन अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर ओड़िसा से आ रहे ट्रक को रोककर तलाशी ली गई।जिसमें दो व्यक्तियों से गहन पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर ड्रायवर सीट में बैठे व्यक्ति अपना नाम रविशंकर यादव निवासी बिहार और हेल्पर सीट पर बैठे शख्स ने अपना नाम सुनील चौहान निवासी यूपी बताया। उन्होंने ट्रक के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा होने की जानकारी दी। दोनों ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ गांजा को भवानीपटना से 50 किलोमीटर आगे एम रामपुर जंगल बालीगुडा ओड़िसा से लाकर प्रयागराज ले जाया जा रहा है।

धान के बाद किसानों को दलहन की खेती से बढ़ा मुनाफा

कोरबा। धान की फसल में ज्यादा मेहनत और पानी लगने के कारण किसान अब तिलहन और दलहन की तरफ रुझान कर रहे हैं। विभाग की ओर से किसानों को उन्नत बीज प्रदान की जा रही है। ताकि वह धान के स्थान पर मूंग, मसूर, उड़द, मक्का, मूंगफली सहित सब्जियों के साथ तिलहन और दलहन के श्रेणी में आने वाले फसलों को उगा सकें, इसके लिए उन्हें उन्नत बीज भी प्रदान की जा रही है। कृषि विभाग पर कुछ किसानों का ये भी आरोप है कि वो धान की फसल को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। पहली बार दलहन और तिलहन की फसलों को उगाने में थोड़ा रिस्क भी रहता है। फसलों की ठीक तरह से देखभाल और प्रशिक्षण के अभाव में कई बार किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। फिलहाल जो किसान इस खेती को कर रहे हैं। उन्हें सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी भी कहते हैं कि इससे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। धान के फसल की जटिलताएं कम होगी और वह समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे।

जगदलपुर के ग्राम पंचायतों में आज लगेंगी चौपाल

जगदलपुर। जिले में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने और ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए 20 फरवरी को ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाई जाएंगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आकाश छिकारा के द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद पंचायत बकावण्ड की समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष निरीक्षण एवं जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। अधिकारियों को अलग-अलग पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्हें सुबह 10 बजे से अपने निधारित क्षेत्रों में उपस्थित रहकर अनिवार्य रूप से निरीक्षण कार्य प्रारंभ करना होगा। अधिकारियों का यह दल प्रत्यक्ष रूप से आंगनबाड़ ?यों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, उचित मूल्य की दुकानों और निमार्णाधीन कार्यों का जायजा लेगा। इस दौरान मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता और हर घर नल-जल जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2.37 लाख बकाया के लिए 33 उपभोक्ताओं की कटी लाइन

जगदलपुर। विद्युत कंपनी ने बकाया की वसूली के लिए डिस्कनेक्शन अभियान को तेज कर दिया है। इसमें शहर के जगदलपुर जोन में 5 टीमें गठित की गई, जो बकायादारों के घरों में पहुंचकर बकाया की वसूली कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिन उपभोक्ताओं घर एवं उपभोक्ताओं घर एवं प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लगाया गया है, उनका बकाया होने पर रायपुर से सीधे बिजली कनेक्शन काटा जा रहा। इसमें हर दिन लगभग 150 बकायादारों की कनेक्शन काटा जा रहा है। हालांकि डिस्कनेक्शन अभियान पर जगदलपुर जोन में दो लाख 37 हजार 150 रुपए बकाया के लिए 33 उपभोक्ताओं की लाइन काटी और 185 उपभोक्ताओं से 17 लाख 25 हजार 807 रूपए वसूल किया गया। वर्तमान में 8580 उपभोक्ताओं पर लगभग एक करोड़ 22 लाख 10 हजार 395 रूपए का बकाया है। जगदलपुर जोन के सहायक अभियंता विकास कुंजाम ने बताया कि डिस्कनेक्शन अभियान के लिए 5 टीमें गठित की गई है, बकाया वसूली में जुटे हुए हैं। मार्च के चलते अभियान को तेज किया गया है।

मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़ा

■ पहले से शादीशुदा जोड़े ने योजना का लाभ लेने फिर से रचाई शादी

कांकेर। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत 10 फरवरी को गोविंदपुर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक जोड़े ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद योजना का लाभ लेने के लिए दोबारा शादी रचा डाली। सोशल मीडिया पर तस्वीरों के वायरल होने के बाद मामला उजागर हुआ, जिससे सत्यापन तंत्र की गंभीर लापरवाही भी सामने आई है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत प्रेमनगर निवासी सुदीप

विश्वास और ग्राम पीवी 64 निवासी स्वर्णा मिस्त्री ने 3 जून 2025 को सामाजिक रीति-रिवाज से विवाह किया था। विवाह के बाद युवती अपने पति के साथ रह रही थी। इसके बावजूद दोनों ने सामूहिक विवाह योजना में पंजीकृत कर लिया गया, और 10 फरवरी को आयोजित समारोह में एक बार फिर से सात फेरे ले लिए। मामले के उजागर होने के बाद आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। आवेदन सेक्टर हरनगढ़ से किया गया, जबकि नियमानुसार वधू पक्ष की स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र से आवेदन अनिवार्य है। आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सेक्टर सुपरवाइजर ने बिना गहन जांच के आवेदन स्वीकार कर लिया। पंचायत से अविवाहित होने का प्रमाण पत्र तो लिया गया, लेकिन वास्तविक वैवाहिक स्थिति की पुष्टि नहीं की गई। वायरल तस्वीरों में वर-वधू सिंदूर और बंगाली परंपरा के अनुसार पोला पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पहले से विवाहित होने का संकेत देते हैं। गौरतलब है कि योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे में फर्जी पंजीकरण के कारण सरकारी राशि गलत हाथों में चली गई। यह पूरा मामला योजना के सत्यापन तंत्र की बड़ी चूक और लापरवाही को उजागर करता है।

जादू-मंत्र से पैसा कई गुना करने का झांसा, पिता-पुत्र गिरफ्तार

बलौदाबाजार। जादू-मंत्र के जरिए रकम कई गुना बढ़ाने का लालच देकर लाखों रुपये ठगने वाले पिता-पुत्र को थाना पलारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने वर्ष 2022 में ग्राम बलौदी और ग्राम रामपुर के दो अलग-अलग व्यक्तियों से कुल 5 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। आरोपियों के कब्जे से एक मोबाइल फोन और 5 हजार रुपये नगद जब्त किए गए हैं। ग्राम बलौदी निवासी नोहर यादव (57 वर्ष) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2022 में आरोपी पिता-पुत्र उसके घर पहुंचे थे। उन्होंने जादू-मंत्र के माध्यम से पैसे को कई गुना करने का दावा करते हुए 18 अक्टूबर 2022 को उससे 3 लाख रुपये नगद ले लिए।

आरोप है कि रकम वापस करने के बजाय आरोपियों ने छलपूर्वक विश्वास में लेकर धोखाधड़ी की। मामले में थाना पलारी में अपराध क्रमांक 452/2025 के तहत धारा 420

और 34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई। इसी तरह ग्राम रामपुर निवासी पराग कटियार ने भी आवेदन देकर बताया कि 2 नवंबर 2022 को आरोपियों ने उसके घर पहुंचकर जादू-मंत्र से पैसा डबल करने का झांसा दिया और 2 लाख रुपये नगद ले लिए। जब उसने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस पर थाना पलारी में अपराध क्रमांक 454/2025 के तहत धारा 420, 506 और 34 भादवि में मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने थाना प्रभारी पलारी को आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। निर्देशों के पालन में पुलिस टीम ने जांच और पतासाजी करते हुए ग्राम धौराभाठा, थाना खरोरा, जिला रायपुर से आरोपी दीनदयाल जांगड़े (66 वर्ष) और पुरुषोत्तम जांगड़े (35 वर्ष) को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पैसा दोगुना करने का झांसा देकर दोनों प्रार्थियों से अलग-अलग मामलों में कुल 5 लाख रुपये लिए थे। पुलिस ने उनके पास से एक मोबाइल और 5 हजार रुपये नगद बरामद किए हैं।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर किया नमन

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने गुरुवार

को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन किया। उन्होंने समस्त देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने आज रायपुर के तात्यापारा में शिवाजी की प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्जवलन और माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सीमित संसाधनों के बावजूद अदम्य साहस, दूरदृष्टि और संगठन क्षमता के बल पर एक सुदृढ़ एवं लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना की। उनका प्रशासनिक ढांचा न्याय, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर आधारित था। आयोजन समिति द्वारा इस अवसर पर राज्यपाल को मराठा योद्धा सम्मान स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, श्री सुनील सोनी एवं आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे।

कुरुद से अभनपुर के बीच नई ब्रॉड गेज लाइन का स्पीड ट्रायल किया गया

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल

मंडल में कुरुद से अभनपुर के बीच 22 किलोमीटर नई ब्रॉड गेज लाइन का स्पीड ट्रायल स्पेशल ट्रेन से कमिश्नर ऑफ़ रेलवे सेफ्टी (रेल संरक्षा आयुक्त) दक्षिण पूर्व सर्कल, कोलकाता के द्वारा किया गया। कुरुद से अभनपुर के बीच स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे से इसका निरीक्षण किया गया। कुरुद से स्पेशल ट्रेन 16:22 बजे शुरू होकर अभनपुर 16:40 बजे पहुंची और इस दौरान कुरुद से अभनपुर के बीच 22 किलोमीटर की दूरी लगभग 18 मिनट मे पूरा किया गया। इस स्पीड ट्रायल के दौरान कमिश्नर ऑफ़ रेलवे सेफ्टी (रेल संरक्षा आयुक्त) दक्षिण पूर्व सर्कल/ कोलकाता श्री ब्रिजेश कुमार मिश्रा जी, अपर महाप्रबंधक श्री विजय कुमार साहू, मंडल रेल प्रबंधक रायपुर श्री दयानंद जी सहित मंडल शाखा अधिकारी उपस्थित रहे।

देखो अपना देश पुरस्कार वितरण समारोह और पर्यटन शिक्षा एक्सपो 21 को

रायपुर। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के

क्षेत्रीय कार्यालय इंडियाटूरिज़्म, मुंबई द्वारा, रायपुर स्थित होटल प्रबंधन, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान के सहयोग से 21 फरवरी, 2026 को देखो अपना देश – पीपुल्स चॉइस एवं स्कूल प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह तथा पर्यटन शिक्षा एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर-40, उपरवारा, नया रायपुर स्थित संस्थान परिसर में प्रात: 9:30 बजे से किया जाएगा। समारोह में प्रात: 9:30 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक विजेता विद्यार्थियों एवं उनके मार्गदर्शक शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में करियर मार्गदर्शन सत्र, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा परिसर भ्रमण भी आयोजित किया जाएगा। इसी दिन प्रात: 10 बजे से सायं 4 बजे तक मिनी पर्यटन शिक्षा एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। एक्सपो का उद्देश्य विद्यालयी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध करियर अवसरों के प्रति जागरूक करना है। छत्तीसगढ़ के आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारक एक्सपो में भाग लेकर व्यावसायिक संभावनाओं, कौशल विकास के अवसरों तथा उभरते रोजगार विकल्पों की जानकारी प्रदान करेंगे। रायपुर एवं आसपास के विद्यालयों के विद्यार्थियों के एक्सपो में शामिल होने की अपेक्षा है।

केलो परियोजना की वितरक नहरों के लिए 6.04 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा रायगढ़ जिले के विकासखण्ड पुसौर के अंतर्गत केलो परियोजना की दो वितरक नहरों के कार्यों के लिए 6 करोड़ 4 लाख 45 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। स्वीकृत कार्यों के टेंगापाली वितरक नहर के आर.डी. 600 मीटर से 1200 मीटर तक सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग कार्य के लिए 3 करोड़ 67 लाख 87 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के प्रस्तावित कार्यों के पूरा हो जाने पर रूपांकित सिंचाई क्षेत्र 885 हेक्टेयर में 261 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। केलो परियोजना की शारदा वितरक नहर के आर.डी. 5000 मीटर से 8340 मीटर तक सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग कार्य हेतु दो करोड़ 36 लाख 58 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के अंतर्गत रूपांकित सिंचाई क्षेत्र 1267 हेक्टेयर में किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। सिंचाई योजनाओं के कार्यों को कराने के लिए मुख्य अभियंता मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना जल संसाधन विभाग बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

छत्तीसगढ़ क्रेडाई के राज्यस्तरीय सम्मेलन में जुटे प्रदेशभर के डेव्हलपर्स

अब भवनों की होगी डिजिटल रैंकिंग, सरकार का दावा रिफॉर्म 2.0 से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर, कई बड़ी मांगें पूरी करने की मांग

रायपुर। ट्राई की पहल पर भारत सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन के साथ क्रेडाई छत्तीसगढ़ द्वारा भवनों की डिजिटल रैंकिंग पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार होगा जब भवनों की डिजिटल रैंकिंग भी होगी। इस तरह का पूरे देश में यह पहला सेमिनार छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार होगा जब भवनों की डिजिटल रैंकिंग भी होगी इससे सरकार की योजनाओं पर भी असर होगा। केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद भी इस रैंकिंग पर निर्भर रहेगी। इसे विस्तार से समझाने के लिए इस सेमिनार में ट्राई के वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली से एवं उनके सलाहकार भोपाल से आये थे।

मंगलवार को राज्य के आला अफसरों के साथ छत्तीसगढ़ क्रेडाई के बिल्डर एकजुट हुए। होटल सैयाजी में आयोजित स्टेट कॉन्फ्रेंस में नए नियमों के साथ ही आवास नीतियों पर खुलकर चर्चा हुई। कई महीनों के बाद ऐसा हुआ जब बिल्डरों ने सरकार के जिम्मेदार अफसरों से सीधे सवाल कर जवाब मांगा। बड़े अफसरों के एक साथ एक मंच पर आने की वजह से क्रेडाई छत्तीसगढ़ ने शासन को सुझाव दिए। अफसरों ने कहा छत्तीसगढ़ में रिफॉर्म 2.0 पर काम हो रहा है। इससे रियल एस्टेट का कारोबार अपनी नई ऊंचाइयों को छुएगा।

कार्यक्रम की शुरुआत में आईटी विभाग के ज्वाइंट सेक्रेट्री आईएएस प्रभात मलिक ने बताया कि अभी तक छत्तीसगढ़ समेत देशभर में ऐसा होता आया है कि नए भवन, बिल्डिंग, अपार्टमेंट बन जाते हैं, लेकिन वहां नेटवर्क और आईटी की कई समस्याएं होती हैं। इसलिए केंद्र सरकार के उपक्रम ट्राई ने छत्तीसगढ़ समेत देशभर के सभी राज्यों से कहा है कि अब उनके प्रोजेक्ट की डिजिटल रैंकिंग भी होगी। इससे बिल्डरों के साथ ही सरकार को भी नंबर मिलेंगे। इसी रैंकिंग से सब्सिडी भी तय की जाएगी। जिस तरह से ग्रीन एनर्जी भवनों को बढ़ावा दिया जा रहा है उसी तरह डिजिटल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी तक पूरे देश में इस तरह के नियम नहीं बने हैं कि आवासीय/कमर्शियल योजनाओं में डिजिटल नेटवर्क के लिए सिस्टम बनाने की व्यवस्था एवं टावर लगाने के स्थान नियत किये जाएं। इस हेतु ट्राई सुझाव लेकर नियम बनाएगा। लेकिन अब से सभी योजनाओं में डिजिटल की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम करने ही होंगे। कार्यक्रम में विशेष रूप से आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, छत्तीसगढ़ क्रेडाई अध्यक्ष पंकज लाहोटी, सचिव अभिषेक बच्छावत सहित विजय नाथानी, राकेश पांडे, संजय बघेल, मृणाल गोलेच्छा, संजय रहेजा, रवि फतनानी, टाउन प्लानिंग के संदीप बांगड़े, विनित नायर आदि मौजूद थे। इस प्रोग्राम को ऋत्विक नाथानी और सुमित बरडिया ने कंडक्ट किया।

टाउन एंड प्लानिंग विभाग के कमिश्नर आईएएस अवनीश कुमार शरण ने बताया कि बिल्डरों को राहत देने सिंगल विंडो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। अभी तक किसी भी हाउसिंग या कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए नजूल, तहसील, नगर पालिका या नगर निगम, बिजली कंपनी और लोक निर्माण विभाग समेत कई और विभागों से दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए सिंगल विंडो खोल दिया है। टाउन प्लानिंग की वेबसाइट में इस सिंगल विंडो में आवेदन करने के साथ ही 100 दिन में प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा रही है। इससे पहले कई महीने लग जाते थे। परेशानी भी बहुत होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इससे प्रोजेक्ट समय पर शुरू होते हैं। लागत भी नहीं बढ़ती। इसका फायदा आम लोगों को भी हो रहा है।

छत्तीसगढ़ क्रेडाई ने मांगी राहत

कॉलोनाइजर नियम अभी तक निगम और पंचायत में अलग-अलग है। इसे एक करना चाहिए।

कमर्शियल लैंड में आवासीय प्रोजेक्ट की भी अनुमति देनी चाहिए। इससे सबको फायदा है।

राज्य में मध्य प्रदेश की तरह समस्त निगमों एवं ग्राम पंचायतों हेतु एक ही कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन रखे जाने की मांग की गई।

राज्य में महाराष्ट्र की तरह Step Setback के प्रावधान लागू किये जाने की गई। महाराष्ट्र की तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी Redevelopment के नियम बनाने की मांग भी की गई। यह सेमिनार कई दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा एवं रियल एस्टेट के कई अन्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई जिसके भविष्य में दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे।

राज्य सरकार शासकीय शालाओं में शिक्षा की गुणवत्ता और योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर पूरी तरह सजग है : कश्यप

■ **प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज आंदोलित अभ्यर्थियों को गुमराह करने की ओछी राजनीति कर रहे हैं**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने सहायक शिक्षक भर्ती-2023 के मसले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पर जमकर निशाना साधा है। श्री कश्यप ने कहा है कि बुधवार को आधी रात को राजधानी के सेंट्रल जेल पहुँचकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष घड़ियाली आँसू बहाकर इस मुद्दे पर आंदोलित अभ्यर्थियों को गुमराह करने की ओछी राजनीति कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में बी.एड. वालों को प्रवेश देकर डी.एड. डिप्लोमाधारकों के भविष्य को संकट में डाला और इस अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले कई अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिससे उनके सरकारी नौकरी पाने के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा।

कश्यप ने कहा कि बैज को यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस शासनकाल

में शिक्षाकर्मियों और विशेषकर डीएड अभ्यर्थियों का मुद्दा जब आंदोलन के रूप में सड़कों पर सामने आया तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सम्वाद का रास्ता चुनकर समस्या का समाधान करने के बजाय प्रशासन की आड़ में टकराव और बल प्रयोग कर लाठीचार्ज किया था। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए श्री कश्यप ने कहा है कि राज्य सरकार शासकीय शालाओं में शिक्षा की गुणवत्ता और योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर पूरी तरह सजग है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नए अभ्यर्थियों के हितों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। न्यायालय के निर्देशानुसार, सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के पाँचवें चरण में 2621 बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों के स्थान पर डी.एड. अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया गया था। शासन के निर्देशों का पालन करते हुए कुल 2615 पदों के लिए अवसर प्रदान किया गया, जिसमें से 1319 अभ्यर्थी पात्र पाए गए और उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षक सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत पाँचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के स्थापन पर डी.एड. अर्हताधारियों अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया गया था। शासन के निर्देशानुसार पाँचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया में 2621 अभ्यर्थियों के स्थान पर 2615 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर प्रदान किया गया था। उक्त भर्ती में 1319 अभ्यर्थी पात्र हुए, जिन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। अब उक्त भर्ती के रिक्त रह गए 1302 पदों के लिए मेरिट के निचले क्रम के अभ्यर्थियों द्वारा छठवें चरण की सूची जारी करने की मांग की जा रही है। श्री कश्यप ने कहा कि पाँचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया में सामान्य श्रेणी का कटऑफ रैंक 6666, अनुसूचित जाति का कटऑफ रैंक 10990, अनुसूचित जनजाति का कटऑफ रैंक 72852 एवं अन्य पिछडा वर्ग का कटऑफ रैंक-9193 आ चुका है।

उपभोक्ता संरक्षण पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन 21 से

■ **ई-कॉमर्स से जुड़ी चुनौतियों के साथ एआई के उपयोग पर होगा गहन मंथन**

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की ओर से केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सहयोग से दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन 21 व 22 फरवरी को रायपुर में किया जा रहा है।

दो दिनों तक आयोजित छह तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन ई-जागृति, ई-फाइलिंग, ई क्क हियरिंग एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, शिकायतों की स्वीकृति, क्षेत्राधिकार एवं प्रक्रिया संबंधी प्रावधान, डिजिटल एवं ई-कॉमर्स चुनौतियाँ, डार्क पैटर्न्स एवं भ्रामक विज्ञापन के साथ उपभोक्ता आयोग के आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सुधार पर चर्चा होगी।

अगले दिन 22 फरवरी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में आवश्यक संशोधन के साथ उपभोक्ता आयोगों में प्रक्रियात्मक एकरूपता की आवश्यकता पर चर्चा होगी। समापन सत्र में खुला संवाद होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की

उपस्थिति में वैलेडिक्टरी (विदाई) सत्र आयोजित होगा।

दो दिवसीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, झारखण्ड, गोवा, बिहार, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा एवं उनके जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, 8 राज्यों के सचिवगण तथा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि इस कार्यशाला में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने यह बताया कि आगामी सप्ताह में रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग में एक अतिरिक्त पीठ एवं बेमेतरा जिले में जिला उपभोक्ता आयोग का शुभारंभ होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला उपभोक्ता आयोगों ने 2025 में 160 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया है, एवं राज्य उपभोक्ता आयोग के निराकरण का प्रतिशत 101 ।57 प्रतिशत रहा। प्रदेश के 16 जिला उपभोक्ता आयोगों में ई-हियरिंग की सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है।

उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला तकनीशियनों की नियुक्ति

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन के 260 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। परीक्षा का आयोजन व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा किया गया था। दावा-आपत्ति के निराकरण के बाद उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा अंतिम चयन एवं अनुपूरक सूची का प्रकाशन किया गया। जारी आदेश के अनुसार, अंतिम चयन सूची से पदस्थापना हेतु आयोजित काउंसिलिंग में अनुपस्थित रहने वाले 14 अभ्यर्थियों, लिखित रूप से त्यागपत्र देने वाले 4 अभ्यर्थियों तथा निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले 10 अभ्यर्थियों के स्थान पर अनुपूरक सूची से 24 अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया गया। वहीं 2 अभ्यर्थी काउंसिलिंग में अनुपस्थित रहे तथा भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग श्रेणी के 1-1 पद उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण रिक्त रखे गए हैं।

इन पदों में चयनित अभ्यर्थियों को मैट्रिक्स लेवल-6 (रू. 25300-80500) वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। उन्हें तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर संबंधित शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार धीरज प्रजापति को बेरला बेमेतरा,गितेश अग्रवाल को जशपुर,निकिता दुबे को किरंदुल दंतेवाड़ा,उमा शंकर पाण्डेय को रामानुजगंज बलरामपुर-रामानुजगंज, प्रह्लाद को छुरा गरियाबंद, अदिति सिंह को रामचंद्र बलरामपुर-रामानुजगंज, अंनिल साहू को गरियाबंद, सोमनाथ यादव को गंडई खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, लक्ष्मी साहू को चांदनी बिहारपुर सूरजपुर, सुधा यादव को छुरिया राजनांदगांव, प्रतिम सिंह को सनावल बलरामपुर-रामानुजगंज, सहदेव सिंह मरावी को मानपुर मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, नरेश कुमार को तोकापाल बस्तर शासकीय महाविद्यालय में पदस्थापना की गई है।

संरक्षा के सजग प्रहरियों को महाप्रबंधक ने किया सम्मानित

रायपुर। रेल परिचालन में संरक्षा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सजगता एवं बेहतर संरक्षा कार्य में सहभागिता निभाने वाले रेल संरक्षा के सजग प्रहरी कर्मचारियों का सम्मान महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा हर माह आयोजित संरक्षा बैठक के दौरान किया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार संरक्षा के सजग प्रहरियों को महाप्रबंधक, तरुण प्रकाश ने सम्मानित किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत संरक्षा कोटि के 7 कर्मचारियो को उनके उत्कृष्ट एवं सराहनीय संरक्षा संबंधी कार्य निष्पादन के लिए महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश के द्वारा सम्मानित किया गया।

बिलासपुर रेल मण्डल के ट्रैक मैंटेनर-।।/ बाराद्वार श्री हिमांशु ने 11 जनवरी, 2026 को अपने ड्यूटी के दौरान सक्ती – बाराद्वार सेक्शन के बीच रात्रि में ट्रैक पैट्रोलिंग के दौरान अप लाइन में किलो मीटर नं.- 645/17 पर रेल फ्रेक्चर देखा और तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधित को दिया जिसके उपरांत आवश्यक कार्यवाही कर ट्रैक को ठीक किया गया। इस प्रकार श्री हिमांशु की सजगता एवं सतर्कता से ट्रेन परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित

हुई। बिलासपुर रेल मण्डल के ट्रैक मैंटेनर-।।/नैला श्री चन्दन कुमार ने 29 जनवरी, 2026 को अपने ड्यूटी के दौरान माल गाड़ी के इंजन से तीसरा वैगन में हॉट एक्सल देखा, तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधित को दिया, जिसके उपरांत आवश्यक कार्यवाही कर गाड़ी को सुरक्षित रवाना किया गया। इस प्रकार श्री चन्दन कुमार की सजगता एवं सतर्कता से ट्रेन परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित हुई।

रायपुर रेल मण्डल के लोको चालक (गुड्स)/भाटापारा खिलेश्वर कुमार ने 28 जनवरी, 2026 को अपने ड्यूटी के दौरान निरीक्षण करते समय लोको इंजिन के इंटरमीडियट कैब बफर हाउसिंग मे दरारें एवं टूटे हुए हिस्से को देख कर तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधित को दिया। जिसके उपरांत आवश्यक कार्यवाही कर गाड़ी का सुरक्षित संचालन किया गया। इस प्रकार श्री खिलेश्वर कुमार की सजगता एवं सतर्कता से ट्रेन परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित हुई।

नागपुर रेल मण्डल के की-मैन / चांदाफोर्ट, अश्विन भास्कर गोवर्धन ने 20 दिसम्बर, 2025 को अपने ड्यूटी के दौरान रजोली-मूलमरोड़ा सेक्शन में ड्यूटी के दौरान किलो मीटर नं.- 1185/20-21 में वेल्ड फ्रेक्चर देखा और तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधित को दिया जिसके उपरांत आवश्यक कार्यवाही कर ट्रैक को ठीक किया गया। इस प्रकार श्री अश्विन भास्कर गोवर्धन की सजगता एवं सतर्कता से ट्रेन परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित हुई।

नागपुर रेल मण्डल के की-मैन/चंदाफोर्ट श्री विश्राम साहु ने 21 दिसम्बर,2025 को अपने ड्यूटी के आलेवाही-सिंदेवाही सेक्शन में ड्यूटी के दौरान किलो मीटर नंबर 1163/2-3 में वेल्ड फ्रेक्चर देखा और तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधित को दिया जिसके उपरांत आवश्यक कार्यवाही कर ट्रैक को ठीक किया गया। इस प्रकार श्री विश्राम साहु की सजगता एवं सतर्कता से ट्रेन परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित हुई।

हर घर नल, हर घर जल का साकार हुआ सपना

घर-घर पहुँच रहा पानी, बदली ठरकपुर की कहानी

रायपुर। जल जीवन मिशन से मुंगेली जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर ग्राम ठरकपुर में हर घर नल, हर घर जल का सपना साकार हुआ है। मिशन के अंतर्गत ठरकपुर में पाइपलाइन बिछाकर प्रत्येक घर को नल कनेक्शन प्रदान किया गया है। इसके बाद से गांव में न केवल पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है, बल्कि पानी की गुणवत्ता और नियमितता भी बेहतर हुई है। अब गांव के हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। इसने ठरकपुर की कहानी बदल गई है।

कभी पेयजल संकट से जूझने वाले ठरकपुर की तस्वीर आज पूरी तरह बदल चुकी है। एक समय था जब पानी के लिए हैंडपंपों पर लंबी कतारें, मटकों

और बाल्टियों के साथ ग्रामीणों की भीड़ तथा गर्मी के दिनों में गांव में जल संकट होता था। पहले पूरा गांव पेयजल के लिए 8 हैंडपंपों के भरोसे था। गर्मियों में जलस्तर गिरने से ये हैंडपंप अक्सर जवाब दे जाते थे, जिससे ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को दूर-दराज के जल स्रोतों से पानी लाने मजबूर होना पड़ता था। ठरकपुर की श्रीमती गंगा यादव बताती हैं कि पहले छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर दूर हैंडपंप से पानी लाना पड़ता था। गर्मी में बहुत परेशानी होती थी। अब घर में नल लग गया है, भरपूर पानी मिल रहा है और जीवन आसान हो गया है। नल जल योजना से महिलाओं की मेहनत और समय की बचत हो रही है, जिसे अब वे परिवार, बच्चों की देखभाल और अन्य रचनात्मक कार्यों में लगा पा रही हैं, इससे वहां की महिलाओं के चेहरे में मुस्कान आई है। ठरकपुर में जल जीवन मिशन केवल पानी की व्यवस्था नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सुविधा और सम्मान का माध्यम बनकर आया है। स्वच्छ जल से बीमारियों में कमी आई है और ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 2 (छत्तीसगढ़)

ई-प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना
(द्वितीय आमंत्रण)

दिनांक 16.02.2026

निम्नांकित कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदा "डी" एवं अधिक श्रेणी के ठेकेदारों के लिये आमंत्रित की जाती है। निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 02.03.2026 तक है।

एन.आई.टी. क्र. / निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3
NIT NO. 297 Tender No. 185713	धमतरी अनुविभाग के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में रोड मार्किंग साईन बोर्ड का कार्य।	रू. 45.00 लाख

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in अथवा विभागीय वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। (राशि रू. 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र एवं न्यूनतम राशि रू. 10.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम पर एनेक्जर-3 का शपथ पत्र, बिड केपेसीटी उपलब्धत्ता बाबत् जानकारी एवं अन्य जानकारी एनआईटी के 2.10 में संलग्न संशोधित प्रपत्रानुसार प्रस्तुत करें।)

निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा, एवं निविदाकारों द्वारा प्रेषित मूल अभिलेख का लिफाफा में निविदाकारों का मोबाईल नं. एवं इमेल आई.डी. का उल्लेख अनिवार्य रुप से करें।

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़
आपकी थी चाह, हमने बनाई राह

जी-252606765/3

अधीक्षण अभियंता,
लो.नि.वि. रायपुर मण्डल. क्र. 2 (छ.ग.)

एआई समिट में मोदी की मेगा डिप्लोमेसी

नीरज कुमार दुबे

एआई इम्पैक्ट समिट में भागीदारी के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समानांतर रूप से एक सक्रिय कूटनीतिक मिशन भी साधते दिख रहे हैं। समिट से इतर विभिन्न देशों के नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकातें इस बात का संकेत हैं कि भारत वैश्विक मंचों का उपयोग केवल बहुपक्षीय चर्चाओं तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि उन्हें रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के अवसर में भी बदल रहा है। डिजिटल तकनीक, व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार जैसे मुद्दों पर हुई ये वार्ताएं बताती हैं कि मोदी सरकार भविष्य की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए साझेदारियां गढ़ रही है और भारत की वैश्विक भूमिका को लगातार विस्तार दे रही है। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ताओं की बात है तो आपको बता दें कि उनकी और एस्टोनिया के राष्ट्रपति की मुलाकात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) इम्पैक्ट समिट के इतर ऐसे समय हुई जब डिजिटल सहयोग वैश्विक कूटनीति का अहम आधार बनता जा रहा है। दोनों नेताओं ने भारत-एस्टोनिया संबंधों की विभिन्न धाराओं की समीक्षा की और खास तौर पर डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई-गवर्नेंस और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की वार्ताओं के ऐतिहासिक समापन और उसके शीघ्र क्रियान्वयन पर भी सहमति जताई गई। सामरिक दृष्टि से एस्टोनिया, जो डिजिटल गवर्नेंस में विश्व अग्रणी माना जाता है, भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए उपयोगी साझेदार है। बाल्टिक क्षेत्र में एस्टोनिया के साथ मजबूत रिश्ते भारत की यूरोप नीति को भी मजबूती देते हैं। वहीं सर्बिया के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, निवेश, एआई, फिनटेक, शिक्षा, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत और सर्बिया के संबंध ऐतिहासिक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौर से ही मित्रतापूर्ण रहे हैं, जिनकी नींव आपसी विश्वास और जन-जन के रिश्तों पर टिकी है। सामरिक रूप से सर्बिया दक्षिण-पूर्व यूरोप में एक महत्वपूर्ण देश है, जहां भारत अपनी आर्थिक और तकनीकी उपस्थिति बढ़ाकर यूरोपीय बाजारों तक पहुंच मजबूत कर सकता है। रक्षा उद्योग, फार्मा और आईटी सेक्टर में सहयोग की संभावनाएं भी भारत के लिए दीर्घकालिक लाभ का आधार बन सकती हैं। उधर, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में भारत-क्रोएशिया संबंधों को नई ऊंचाई देने पर जोर दिया गया। एआई, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा जैसे भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने भारत-ईयू एफटीए को जल्द लागू करने की जरूरत दोहराई। क्रोएशिया के लोगों में भारतीय संस्कृति, योग और आयुर्वेद के प्रति बढ़ती रुचि का भी उल्लेख हुआ, जो सॉफ्ट पावर के जरिए संबंधों को गहरा करता है। सामरिक नजरिए से क्रोएशिया एड्रियाटिक सागर क्षेत्र का अहम देश है और यूरोप में लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भारत के लिए अवसर खोलता है। इसके अलावा, स्पेन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात बहुआयामी साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित रही। रक्षा, सुरक्षा, तकनीक, नवाचार, स्वास्थ्य, जलवायु कार्रवाई और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। 2026 को भारत-स्पेन संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने की पहल दोनों देशों के रिश्तों को जनस्तर तक ले जाने का प्रयास है। विश्वविद्यालयों के बड़े प्रतिनिधिमंडल का भारत आना अकादमिक और शोध सहयोग की संभावनाएं बढ़ाता है।

ट्रिपल इंजन से बदलेगी दिल्ली की तस्वीर

ललित गर्ग

वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में दिल्ली के लिए 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का प्रावधान केवल एक आर्थिक घोषणा नहीं, बल्कि राजधानी के भविष्य की रूपरेखा है। सड़क, रेल परिवहन, मेट्रो विस्तार, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और पुलिस व्यवस्था जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान यह संकेत देता है कि केंद्र सरकार दिल्ली को एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और आदर्श महानगर के रूप में विकसित करना चाहती है। ऐसे समय में जब दिल्ली की भाजपा सरकार अपना एक वर्ष पूर्ण कर रही है, यह स्वाभाविक है कि बीते वर्ष के कामकाज का मूल्यांकन किया जाए और देखा जाए कि तथाकथित ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ दिल्लीवासियों को कितना और कैसे मिला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों और आगामी संकल्पों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने न केवल नई योजनाओं की शुरुआत की, बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों की लंबित और अधूरी परियोजनाओं को भी गति दी है। 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना', मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, अधूरी पड़ी आधारभूत परियोजनाओं को पूरा करने की पहल, तथा महिलाओं और छात्रों के लिए नई राहतकारी योजनाओं का खाका-ये सब उनके पहले वर्ष के प्रमुख बिंदु रहे। उनका यह भी कहना है कि ट्रिपल इंजन की व्यवस्था-अर्थात केंद्र, राज्य और नगर निकाय में एक ही राजनीतिक नेतृत्व के कारण विकास कार्यों में समन्वय और गति दोनों आई है।

ट्रिपल इंजन सरकार की अवधारणा का सबसे बड़ा लाभ वित्तीय समन्वय के रूप में सामने आया है। दिल्ली सरकार को अब पूंजीगत व्यय के लिए ऋण अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो रहा है। पहले जहां ब्याज दर 13-14 प्रतिशत तक पहुंच जाती थी, वहीं अब लगभग सात प्रतिशत पर ऋण मिलना संभव हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा 21 हजार करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा निर्धारित किए जाने से आधारभूत ढांचे के विकास में धनाभाव की आशंका कम हुई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन तथा पीएम भीम योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं की समयावधि बढ़वाने में भी दिल्ली सरकार को सफलता मिली है। आयुष्मान भारत जैसी जनकल्याणकारी योजना का लाभ अब राजधानी के अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंच रहा है, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा की ठोस गारंटी मिल रही है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के संकेत अवश्य दिखाई दिए हैं। मोहल्ला क्लीनिक मॉडल पर उठे प्रश्नों और अधूरी स्वास्थ्य परियोजनाओं के बीच नई सरकार ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण, बेड क्षमता बढ़ाने और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यदि यह प्रयास निरंतरता से जारी रहा तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के अनुरूप विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार का दावा किया गया है। पिछले वर्षों में शिक्षा मॉडल को लेकर जहां एक ओर प्रशंसा हुई, वहीं भवनों की गुणवत्ता, संसाधनों के उपयोग और परिणामों पर सवाल भी उठे। नई सरकार के लिए यह चुनौती है कि वह शिक्षा को राजनीतिक विमर्श से ऊपर उठाकर वास्तविक गुणवत्ता सुधार की दिशा में कार्य करे।

परिवहन और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी गति लाने का प्रयास हुआ है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, बस बेड़े के आधुनिकीकरण और सड़कों के सुधार की योजनाएं केंद्र और राज्य के समन्वय से आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली मेट्रो पहले से ही राजधानी की जीवनरेखा रही है, अब किराए में राहत या छात्रों के लिए विशेष प्रावधान जैसे कदम यदि लागू होते हैं तो इससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए फ्लाईओवर, अंडरपास और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली पर ध्यान देना आवश्यक है। एक वर्ष में कुछ परियोजनाओं को गति मिली है, किंतु राजधानी जैसे विशाल महानगर में ठोस परिणामों के लिए निरंतर प्रयास अपेक्षित हैं।

सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण और वायु प्रदूषण की है। बीते दशक में दिल्ली विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में गिनी जाने लगी। यह केवल आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य का संकट है। मुख्यमंत्री ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस योजनाओं का उल्लेख किया है-जैसे हरित आवरण बढ़ाना, निर्माण कार्यों पर निगरानी, सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन और पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय। परंतु यह भी सत्य है कि प्रदूषण जैसी जटिल समस्या का समाधान केवल घोषणाओं से संभव नहीं, इसके लिए कठोर क्रियान्वयन, क्षेत्रीय सहयोग और जनसहभागिता की आवश्यकता होगी। यमुना की सफाई भी दिल्ली की अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है। वर्षों से यमुना शुद्धिकरण के नाम पर योजनाएं बनती रहीं, बजट खर्च होता रहा, पर परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। वर्तमान सरकार ने यमुना को स्वच्छ और पर्यटन योग्य बनाने का संकल्प दोहराया है। यदि सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण और नदी तट के पुनर्विकास की योजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू होती हैं, तो यह दिल्ली की छवि को नया आयाम दे सकती हैं। यमुना का पुनर्जीवन केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक पुनरुत्थान का भी अवसर है।

महिलाओं और बेटियों के लिए घोषित योजनाएं-जैसे 'लखपति बिटिया योजना'-सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक कदम मानी जा सकती हैं। यदि इन योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पारदर्शिता से पहुंचता है, तो यह परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और शिक्षा के अवसरों को बढ़ा सकता है। मुफ्त एलपीजी सिलेंडर जैसी पहल घरेलू अर्थव्यवस्था में राहत देती है, विशेषकर निम्न आय वर्ग के लिए। किंतु इन योजनाओं की सफलता क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। एक वर्ष की अवधि किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी नहीं होती, विशेषकर तब जब उसे पिछली सरकारों की अधूरी परियोजनाओं और व्यवस्थागत खामियों को भी दुरुस्त करना हो। यह भी सच है कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच विकास का वास्तविक आकलन कठिन हो जाता है। नई सरकार ने पूर्ववर्ती शासन की कमियों-जैसे कथित भ्रष्टाचार, अधूरी इमारतें, प्रदूषण नियंत्रण में विफलता को सुधारने का दावा किया है। किंतु जनता अब केवल आरोप नहीं, परिणाम देखना चाहती है। आने वाले वर्षों के लिए सरकार के सामने स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए-स्वच्छ वायु, स्वच्छ यमुना, सुगम यातायात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य और पारदर्शी प्रशासन। राजधानी होने के नाते दिल्ली को केवल भारत का प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि आदर्श शहरी मॉडल बनना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि बजट में आवंटित राशि का पूर्ण और पारदर्शी उपयोग हो, परियोजनाएं समयबद्ध पूरी हों और जनभागीदारी को प्रोत्साहन मिले।

ट्रिपल इंजन सरकार का वास्तविक अर्थ तभी सिद्ध होगा जब समन्वय का लाभ जमीन पर दिखाई दे। केंद्र और राज्य के बीच टकराव की राजनीति के स्थान पर सहयोग की भावना यदि कायम रहती है, तो दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकती है। एक वर्ष में कुछ सकारात्मक संकेत अवश्य मिले हैं, परंतु अभी लंबी यात्रा शेष है। सरकार को अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने के साथ-साथ कमियों का ईमानदार आत्ममंथन भी करना होगा। दिल्ली की जनता जागरूक है और अपेक्षाएं भी बड़ी हैं। वह केवल वादों से संतुष्ट नहीं होगी, उसे परिणाम चाहिए। यदि रेखा गुप्ता सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतारने में सफल होती है, तो आने वाले वर्षों में दिल्ली सचमुच एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित और आधुनिक महानगर के रूप में उभर सकती है। यही समय है जब बजट की घोषणाओं को विकास की वास्तविक कहानी में बदला जाए और राजधानी को समस्याओं के प्रतीक से समाधान के मॉडल में परिवर्तित किया जाए।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

इनके विचार में पदार्थ-विज्ञान के सम्बन्ध में जो कुछ खोज इस युग में हुई है वह मानो अभूतपूर्व है। आज से पहिले- इसप्रकार की बातें हिन्दुओं के पूर्वज जानते तक न थे!! इसप्रकार की निर्मूल धारणा न केवल अहिन्दू समाज में ही बल्कि उनकी देखादेखी संस्कृत साहित्य से अपरिचित अदूरदर्शी हिन्दुओं में भी एक हद्द तक परिपक्व सी हो गई है परन्तु भला हो वेदव्यास जी का!

जो कि वेदोंके गूढ़तत्त्वों का खुलासा पुराणों के रूप में हमारे लिये छोड़ गये हैं। हम श्रीमद्भागवत पुराण की उपर्युक्त एक ही कथा के बल पर संसार भर के विज्ञानवेत्ताओं को खुला चैलेञ्ज देते हैं कि कोई माई का लाल बतलाए कि-सोना चाँदी आदि धातुवें किस मूलतत्त्व-मादे से और किस प्रकार बनी हैं? उक्त घातुओं के परमाणु पुंज किन 2 तत्त्वों के घनीभाव का परिणाम हैं? एवं ये सब धातुवें पृथ्वी के अमुक 2 भाग में ही आधिक्य से क्यों निवलती है? सर्वत्र समान रुप से रुपलब्ध क्यों नहीं होतीं? इत्यादि। शंकाशूर समाजी, नमाजी और पुराण-निन्दवा गाजी इन प्रश्नों को सुनकर शीतलावाहन के सींगों की तरह तत्काल रफू-चक्कर हो जायेंगे।

वास्तव में श्रीमद्भागवत के इस आख्यान में आलङ्कारिक पद्धति से सोने चाँदी की उत्पत्ति का ही वैज्ञानिक विवेचन किया गया है।

वैदिक स्वरूप में बतलाया गया है अग्नि सोम और आप इन तीन मूल तत्त्वों के संघात से सोना उत्पन्न हुआ है।

पुराणों में इन्हीं तीनों पदार्थों का तारतम्य प्रकट करके कौन पदार्थ किस रूप में परिवर्तित हुआ इस गूढ़ विज्ञान को सर्वसाधारणोपयोगी एवं अतीव सरल बनाने के लिये विष्णु मोहिनी और शिव नाम से स्मरण किया है।

क्रमशः ...

विश्व सामाजिक न्याय दिवस

अनन्या मिश्रा

हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के बीच समानता और न्याय को बढ़ावा देना है। इस दिन सामाजिक असमानता, भेदवाद, बेरोजगारी और मानवाधिकारों के हनन जैसे मुद्दों को लेकर लोगों में जागरुकता फैलाई जाती है। क्योंकि असल में कोई देश तब विकास करता है, जब उसके नागरिकों को एक समान अधिक प्राप्त होते हैं। ऐसे में इस दिन का मकसद लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाना है। जिससे कि नागरिक सामाजिक और आर्थिक उन्नति कर सकें।

साल 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दिन दुनियाभर में सामाजिक न्याय, एकजुटता और संसाधनों के समान वितरण को बढ़ावा के प्रयास को मजबूत करने के लिए इस दिन को मनाए जाने का फैसला लिया गया। साल 2009 में पहली बार विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया था। यह दिन गरीबी, असमान व्यवहार और बेराजगारी कम की जरूरतों को ध्यान में रखकर मनाया जाता है।

दुनिया में बढ़ती समस्याओं को देखते हुए आज सामाजिक न्याय की जितनी जरूरत है उतनी पहले शायद पहले नहीं थी। दुनिया में राजनैतिक विभाजन पहले से अधिक हो रहा है एवं समुदायों में असुरक्षा ज्यादा बढ़ती दिख रही है। हम सब मिलकर जाति-धर्म, गरीबी- अमीरी, वंश-वर्ग आदि सारे भेदभाव को भुलाकर एक स्वस्थ एवं आदर्श समाज की स्थापना करें और मानव अधिकारों का सम्मान करें, यही इस दिवस का मूल उद्देश्य है। सामाजिक न्याय की पिच पर ही नई सोशल इंजीनियरिंग तैयार हो सकती है।

यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो आज अधिक प्रासंगिक है। इस संदर्भ में निष्पक्षता का अर्थ है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, न्याय और अन्य के समान मानकों तक समान पहुंच। सभी की इन चीजों के समान मानकों तक समान पहुंच होनी चाहिए, चाहे उनकी जाति, धर्म, लैंगिकता, लिंग या वर्ग कुछ भी हो। विश्व सामाजिक न्याय का मतलब है, ऐसा समाज बनाना जहां सभी लोगों को समान अधिकार, अवसर और व्यवहार मिलें। सामाजिक न्याय के ज़रिए समाज की आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को कम करने की कोशिश की जाती है और सभी नागरिकों को सामाजिक समानता देने के प्रयास किये जाते हैं। समाज की सामान्य भलाई के लिए दूसरों की देखभाल एवं सहायता करने की ज़िम्मेदारी और सभी को अपनी ज़िंदगी में सुधार करने के लिए समान अवसर मिले, इसके लिये यह दिवस एक आह्वान है। सामाजिक न्याय की आकांक्षा, यह सुनिश्चित करती है कि हर कामकाजी पुरुष और महिला को अपने योगदान के मुताबिक उचित हिस्सा मिले, जो सामाजिक न्याय, सामाजिक एकजुटता, आर्थिक विकास, और मानव प्रगति के लिए ज़रूरी है।

भारत की इस 166 किमी जमीन ने हिलाई दुनिया?

अभिनय आकाश

100 बरसों से एक कहावत चली आ रही है। हु रूल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड। मतलब जो लहरों पर राज करेगा दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। इतिहास के पन्नों से गुलाम हिंदुस्तान की यादों तक कई उदाहरण मिल जाएंगे। हजारों साल पहले हड़प्पा सभ्यता में लोथल के रास्ते दुनिया के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ना हो या फिर 1971 में कराची पर ताबड़तोड़ बमबारी से पाकिस्तानी सेना की रीड तोड़ना। इन सब में समंदर ने अहम भूमिका निभाई। अब समुंदर से जुड़ी ऐसी ही खबर सामने आ रही है। 92,000 करोड़ की लागत से एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है जो इंडिया के लिए इंडोपेसिफिक में जियोपॉलिटिक्स का खेल बदलने की कुवत रखता है।

भारत की मुख्य भूमि से 1800 किमी दूर भारत के ही एक इलाके ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। यह इलाका है तो 900 किमी से बड़ा लेकिन इसमें से 166 किमी के दायरे में भारत एक ऐसा काम कर रहा है जो पूरा हो गया तो कई देशों को घुटनों पर ला सकता है। इस इलाके में भारत जो प्रोजेक्ट बना रहा है, वह हमेशा के लिए चीन के गले में रस्सी डाल सकता है। लेकिन आपके होश तब उड़ जाएंगे जब आपको यह पता चलेगा कि भारत के इस सबसे रणनीतिक और कूटनीतिक प्रोजेक्ट्स को रोकने वालों की लिस्ट में चीन से पहले भारत के ही कई तथाकथित एनजीओ शामिल हैं। भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए कोर्ट में मामले को लटकाने की कोशिश हुई। कहा गया कि इस प्रोजेक्ट की वजह से काफी पेड़ काटे जाएंगे। कुछ लोग विस्थापित हो जाएंगे।

16 फरवरी 2026 को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर बन रहे इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। एनजीटी देश का स्पेशल कोर्ट है जो पर्यावरण से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करता है। खैर एनजीटी ने पर्यावरण मंजूरी को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी और विकास के लिए रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी हैं। इसलिए इनमें दखल देना ठीक नहीं होगा।

दक्षिण पूर्व में चारों ओर बंगाल की खाड़ी से घिरे कुल 836 छोटे-बड़े आइलैंड है। इन्हीं को मिलाकर बनता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसी के सबसे नीचे माने दक्षिण में है ग्रेट निकोबार आइलैंड। हरेभरे पेड़, सैकड़ों प्रजातियां, क्रिस्टल क्लियर पानी इस इलाके की पहचान है। लेकिन भारत सरकार इस इलाके में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाने जा रही है। भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है। अब कुछ महीनों में समंदर के बीचों-बीच भारत का यह सबसे रणनीतिक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ?90 हजार करोड़ से ज्यादा की ग्रेट निकोबार परियोजना की रणनीतिक अहमियत को समझते हुए कहा है कि यह प्रोजेक्ट बनना चाहिए। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, मलेशिया के क्लांग बंदरगाह और सिंगापुर से ग्रेट निकोबार की दूरी लगभग बराबर है। लेकिन ग्रेट निकोबार परियोजना की जिस खासियत ने चीन की हवाइयां उड़ा रखी हैं। खासियत इसकी मलक्का की खाड़ी से नजदीकी है। भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मलक्का की खाड़ी यानी मलक्का स्ट्रेट से महज 160 किमी दूर है। मलक्का स्ट्रीट से दुनिया का 1/3 व्यापार गुजरता है।

दुनिया के 40त्न तेल टैंकर ग्रेट निकोबार के हिंद महासागर क्षेत्र से ही होकर गुजरते हैं। आपको बता दें कि चीन की मलक्का स्टेट पर बहुत निर्भरता है। चीन की 80त्न ऊर्जा जरूरतें मलक्का स्टेट से ही पूरी होती हैं। यानी चीन अपनी जरूरत का जितना तेल आयात करता है उसका 80त्न मलक्का स्ट्रेट से ही होकर गुजरता है और यहीं पर भारत आकर बैठ गया है। मलक्का स्ट्रीट के पास मौजूद भारत ग्रेट निकोबार से चीन के हर जहाज पर नजर रख सकता है। फिर चाहे वो चीन का तेल टैंकर हो, जासूसी जहाज हो या फिर मिलिट्री जहाज हो। अभी तक चीन भारत की जासूसी करता था। किन अब भारत चीन की गर्दन पर जाकर बैठ गया है। आपको बता दें कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत भारत इस इलाके में ड्यूल पर्पस एयरपोर्ट बना रहा है। यानी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल सिविल पर्पस के साथ-साथ मिलिट्री पर्पस के लिए भी होगा।

आपको बता दें कि अंडमान निकोबार में पहले से ही भारत की ट्राई सर्विस कमांड है। इसका मतलब यह है कि यहां पर पहले से ही एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों मौजूद हैं और अब इन तीनों को ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। इकोनॉमिक दृष्टि से भी ग्रेट निकोबार भारत के लिए बड़ा खजाना साबित होने वाला है। इस प्रोजेक्ट से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

कहा जा रहा है कि करीब 130 वर्ग किमी से ज्यादा का ट्रॉपिकल रेनफोर्स का एरिया नष्ट होगा। नंबर्स में बात करें तो 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। ऐसा अनुमान है। बड़ी बात यह है कि यहां काटे गए पेड़ों के ऐवज में सरकार हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा में पेड़ लगाएगी। ऐसा उन्होंने अदालत के समक्ष एनजीटी के समक्ष कहा है। जंगल जानवरों का घर है। इसके काटे जाने से लाखों जीव-जंतुओं को खतरा होगा। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी लेदर बैंक कछुए के घोंसले की जगह नष्ट होगी। इसके अलावा निकोबार मेगापॉड पक्षी जो सिर्फ यहीं पर पाया जाता है इनका भी घर छिन जाएगा। इसलिए इन सब के संरक्षण के लिए जरूरी व्यवस्थाएं हो। इसे लेकर तमाम चिंताएं हैं। 20,000 से ज्यादा कोरल रीफ की कॉलोनी भी इससे प्रभावित होंगी। कोरल रीफ समुद्र का वर्ष वन होता है। यहां समुद्र की 1/4 प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इस प्रोजेक्ट से आदिवासियों के जीवन पर भी गंभीर असर पड़ेगा। यह इलाका शोमपेन और निकोबारी आदिवासियों का घर है। एक तरफ सरकार कह रही है कि शोमपेन जनजाति की बस्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

आज का इतिहास

- 1827 इटुजिंगो की लड़ाई (पेसो दो रोजारियो) में ब्राजील के इंपीरियल आर्मी के एक दल ने अर्जेंटीना-उरुग्वेयन सैनिकों से युद्ध में भाग लिया।
- 1846 पोलिश विद्रोहियों ने फ्री सिटी ऑफ क्राकोटो में एक विद्रोह का नेतृत्व किया जो नौ दिनों के बाद ऑस्ट्रियाई साम्राज्य द्वारा रखी गई राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक लड़ाई को उकसाता है।
- 1864 अमेरिकन सिविल वॉर-द यूनियन को लेक सिटी, फ्लोरिडा के पास ओलस्टी की लड़ाई में अपने सबसे खूनखराबे में से एक का सामना करना पड़ा।
- 1869 टेनेसी के गवर्नर डब्ल्यू सी ब्राउनलो ने कु क्लक्स क्लान संकट में मार्शल लॉ की घोषणा की।
- 1872 न्यूयॉर्क शहर का मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ़ आर्ट, आज संयुक्त राज्य में सबसे बड़ा आर्ट म्यूज़ियम है जिसमें दो मिलियन से अधिक कलाओं का संग्रह है, जिसे खोला गया।
- 1873 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने अपना पहला मेडिकल स्कूल खोला।
- 1915 सैन फ्रांसिस्को ने पनामा-प्रशांत अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- 1921 चेकोस्लोवाकिया की युवा कम्युनिस्ट लीग की स्थापना हुई।
- 1943 शनिवार की शाम की पोस्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के फोरफ्रीडम्स के समर्थन में, सबसे व्यापक रूप से वितरित पेंटिंगसेवर में से कुछ नॉर्मनरॉकवेल के फोर फ्रीडम में से पहला प्रकाशित किया।
- 1959 कनाडा के प्रधान मंत्री जॉन डिफेनबर्करकंवर ने बहुत अधिक राजनीतिक बहस के बीच एवरो सीएफ-105 एरो इंटरसेप्टर विमान कार्यक्रम को रद्द कर दिया।
- 1965 नासा के रेंजर 8 अंतरिक्ष यान ने घोड़ी ट्रेंक्विलाटिस में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले अपने मिशन के अंतिम 23 मिनट में चंद्रमा की 7,137 तस्वीरों को सफलतापूर्वक प्रसारित किया।
- 1983 उत्तर पूर्वी राज्य असम में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले व्यापक पैमाने पर हिंसा भड़कने से 600 लोगों की मौत हुई।
- 1988 नागोर्नो-करबाख स्वायत्त ओब्लास्ट ने अज़रबैजान से अलग होने और आर्मेनिया में शामिल होने के लिए वोट किया, जिससे नागोर्नो-करबाख युद्ध शुरू हो गया।
- 1994 20 फरवरी 1994 को 3 अफगान 70 बच्चों को बंधक बना लेते हैं।
- 1997 सैन फ्रांसिस्को दिग्गज बैरी बॉन्ड्स ने 20 फरवरी, 1997 को 22.9 मिलियन डॉलर के दो साल के अनुबंध का रिकॉर्ड बनाया।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 : नवाचार से राष्ट्र निर्माण तक

सुनील कुमार महला

आज का समय तकनीक का समय है, या यूँ कहें कि हम तकनीक के युग में सांस ले रहे हैं। यह तकनीक ही है, जो मनुष्य के जीवन को अधिक सुविधाजनक बना रही है, लेकिन इसके साथ-साथ हमारी सोच, कार्यशैली और आदतें भी आज बदल रही है। कहना ग़लत नहीं होगा कि वर्तमान दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) इस परिवर्तन का सबसे प्रमुख उदाहरण बनकर उभरी है। तेजी से बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच दुनिया भर में आधुनिक तकनीकों के विकास और नवाचार पर विशेष जोर बढ़ा है। आज दुनिया के विभिन्न देश अपनी नीतियों में नई-नई तकनीकों व नवाचारों को शामिल कर अपने देश की विभिन्न पारंपरिक कार्यप्रणालियों को लगातार बदल रहे हैं। विशेष रूप से एआई ने वैश्विक स्तर पर कार्य प्रणाली और मानव भूमिका को गहराई से प्रभावित किया है, इसलिए आज इसे विकास के लिए अनिवार्य और बहुत ही अहम् माना जा रहा है। इसी संदर्भ में, नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण एआई शिखर सम्मेलन(इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026; 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक) आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एआई की संभावनाओं, इसकी चुनौतियों, रोजगार पर इसका प्रभाव और आम जीवन में इसके उपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज एआई का दायरा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, कारोबार और रक्षा जैसे क्षेत्रों तक फैल चुका है, जिससे नए अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि रोजगार पर प्रभाव, जोखिम, डेटा सुरक्षा और पर्यावरणीय असर जैसी चिंताएँ भी इसके कारण सामने आई हैं। विशेष रूप से डेटा केंद्रों में ऊर्जा और पानी की बढ़ती खपत को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। इसलिए एआई आधारित विकास को सफल बनाने के लिए इसके लाभों के साथ-साथ संभावित खतरों के समाधान पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी 2026 तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह पाँच दिवसीय कार्यक्रम ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला प्रमुख एआई शिखर सम्मेलन माना जा रहा है, जिसमें 300 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं और एआई नीति तथा नवाचार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। गौरतलब है कि यह समिट भारत मंडपम सहित नई दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर आयोजित हो रही है तथा इसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी है, साथ ही शीर्ष तकनीकी कंपनियों जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सीईओ), शोधकर्ता, नीति-निर्माता और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के दौरान 500 से अधिक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि 800 से अधिक प्रदर्शक, स्टार्टअप,

शोध संस्थान और राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल इसमें भाग ले रहे हैं।

16-20 फरवरी तक आयोजित यह एआई शिखर सम्मेलन भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआइ) के क्षेत्र में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जबकि उससे आगे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के अनुसार भारत का स्कोर 21.59 है, जबकि अमेरिका का 78.6 और चीन का 36.95 है। इस सूचकांक में भारत कई विकसित देशों जैसे दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस से आगे है। भारत वर्तमान में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ एआई के क्षेत्र में अग्रणी विकासशील देश भी बन चुका है। इसलिए इस स्तर का वैश्विक आयोजन पहली बार किसी विकासशील देश में होना ऐतिहासिक माना जा रहा है। सम्मेलन में 13 देशों के लगभग 300 पवेलियन वाले एक्सपो का आयोजन भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई के माध्यम से आम लोगों तक तकनीक के लाभ पहुँचाने, सस्ती तकनीक उपलब्ध कराने और वैश्विक असमानताओं को कम करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते देश निवेश बढ़ाए, प्रतिभाओं को बनाए रखे और अनुकूल तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करे।

वास्तव में, यह समागम विश्व के सबसे बड़े एआई आयोजनों में से एक माना जा रहा है और ग्लोबल साउथ में आयोजित पहली बड़ी एआई शिखर बैठक के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भारत सहित विभिन्न विकासशील देशों की भूमिका मजबूत होगी। सम्मेलन में एआई आधारित नवाचार, प्रतियोगिताएँ, हैकाथॉन तथा करोड़ों रुपये के पुरस्कार वाले कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे विभिन्न देशों को उद्योग और निवेश के अवसर मिल रहे हैं, साथ ही एआई के वास्तविक उपयोग (एप्लीकेशन), स्टार्टअप सहयोग और व्यापारिक साझेदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यदि हम यहां पर इस समिट के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो, इनमें क्रमशः समावेशी और जिम्मेदार एआई विकास (एआई सभी के लिए और अच्छे के लिए), वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, विकसित और विकासशील देशों के बीच तकनीकी अंतर को कम करना, सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना (स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और पर्यावरण में सुधार), सुरक्षित, विश्वसनीय और नैतिक एआई के लिए अंतरराष्ट्रीय नीति संवाद को आगे बढ़ाना तथा भारत को वैश्विक एआई केंद्र के रूप में स्थापित करना शामिल है।

हालाँकि, एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच एक महत्वपूर्ण मानवीय प्रश्न भी सामने आता है। आज एआई के कारण लिखना तेज और आसान हो गया है, लेकिन इससे वास्तविक रचनात्मकता का अर्थ कुछ हद तक धुंधला पड़ने लगा है। अब लोग केवल लेख की गुणवत्ता नहीं देखते, बल्कि यह भी सोचते हैं कि उसे इंसान ने लिखा है या मशीन ने। यह सच है कि एआई द्वारा तैयार सामग्री अक्सर संतुलित और प्रभावी होती है, लेकिन उसमें वह जीवंतता नहीं होती जो किसी इंसान के अनुभव, संघर्ष और भावनाओं से आती है। एआई प्रेम, पीड़ा या संवेदनाओं की भाषा तो लिख सकती है, पर उसने स्वयं कुछ महसूस नहीं किया होता। इसलिए जब ऐसी रचना किसी व्यक्ति के नाम से प्रस्तुत की जाती है, तो यह बौद्धिक नकल जैसी स्थिति भी पैदा कर सकती है। हमें यह समझना होगा कि वास्तविक सृजन केवल परिणाम नहीं, बल्कि सोचने, गलती करने, सीखने और संघर्ष करने की प्रक्रिया भी है, जिसे एआई छोटा कर देती है। फिर भी; एआई कोई दुश्मन नहीं है। यदि इसे एक ईमानदार औजार की तरह जैसे जानकारी खोजने, विश्लेषण करने या भाषा सुधारने के लिए आदि के लिए उपयोग किया जाए, तो यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसके माध्यम से किए गए कार्य का पूरा श्रेय स्वयं लेने लगते हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि एआई सुविधा अवश्य प्रदान करती है, लेकिन वास्तविक रचनात्मकता आज भी मनुष्य के अनुभव, संघर्ष और ईमानदारी से ही जन्म लेती है।

मोदी और मैक्रों : बहुआयामी साझेदारी की ओर बढ़ते कदम

लव गौर

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा सिर्फ अहम द्विपक्षीय समझौतों के लिहाज से ही नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में दो महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों के बीच भरोसे, साझेदारी और दीर्घकालिक दृष्टि के सार्वजनिक उद्घोष के रूप में भी देखी जा सकती है। इस दौरान, राफेल, पनडुब्बी और हेलिकॉप्टर निर्माण इत्यादि में सहयोग बढ़ाने को लेकर हुए समझौतों के अतिरिक्त मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों ही देश अब बहुस्तरीय, बहुआयामी और वैश्विक स्तर पर प्रभावी साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।

इस साझेदारी के तहत सहयोग के 21 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें रक्षा, एआई, ऊर्जा, शिक्षा, अंतरिक्ष और महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। दोहरे कराधान से बचाव समझौते के प्रोटोकॉल संशोधन पर भी दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो बढ़ती भू-राजनीतिक अस्थिरता, यूक्रेन संकट और हिंद-प्रशांत में चीन की आक्रामकता के बीच भारत और फ्रांस के बीच यह साझेदारी एक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण प्रयास है।

गौरतलब है कि 2017 में फ्रांस के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से मैक्रों की यह चौथी भारत यात्रा है, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत तालमेल को भी दिखाती है। इसके अतिरिक्त, बीती जनवरी में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की यात्रा, इस वर्ष गणतंत्र दिवस में यूरोपीय संघ के नेतृत्व की मौजूदगी और उससे पहले अरसे से लंबित मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति, ये सभी बिंदु भारत के रणनीतिक विजन में यूरोप के बढ़ रहे महत्व को

इंगित करते हैं।

उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली की तरह, पेरिस भी लंबे समय से बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत करता आया है और यही साझा मूल्य दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों का आधार बना हुआ है। हालांकि, इस साझेदारी को कामयाब बनाने के लिए रक्षा सौदों में पारदर्शिता और तकनीकी हस्तांतरण सुनिश्चित करना अहम है। इसके अलावा, जलवायु लक्ष्यों को पाने के लिए फ्रांस की हरित ऊर्जा विशेषज्ञता का फायदा उठाते हुए भारत को अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ानी चाहिए।

उसे अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए बहुपक्षीय संबंधों में संतुलन साधना होगा, वहीं फ्रांस के लिए जरूरी है कि वह, जैसा कि उसने घोषणा भी की है, भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अधिक सक्रिय समर्थन प्रदान करे। कुल मिलाकर, मैक्रों की भारत यात्रा का महत्व सिर्फ द्विपक्षीय गर्मजोशी के लिहाज से नहीं, बल्कि इस रूप में भी है कि बदलती भू-राजनीति के दौर में भारत व फ्रांस ने अमेरिका और चीन से अलग एक तीसरी दिशा के समर्थक के रूप में खुद को प्रस्तुत किया है।

प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राहुल गांधी की कहानी

पूनम आई. कौशिश

उथल -पुथल और शोर-शराबे भरे संसद के बजट सत्र के पहले चरण के दौरान 3 अकल्पनीय घटनाएं हुईं, जिनके चलते यह उच्च कोटि का भावनात्मक राजनीतिक ड्रामा बन गया। प्रश्न उठता है अनहोनी जब होनी हो जाए तब क्या होता है? पहला, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया और जिसका कारण यह बताया गया कि उनके पास विश्वसनीय सूचना थी कि अनेक कांग्रेसी महिला सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंचकर कुछ अभूतपूर्व घटना कर सकती हैं, हालांकि कांग्रेस ने इस बात का खंडन किया।

इससे एक विचारणीय प्रश्न उठता है कि क्या प्रधानमंत्री भारत के लोकतंत्र के पावन मंदिर संसद में असुरक्षित हैं? और यदि हैं तो कैसे और क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को देश में सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है। इसके अलावा संसद परिसर की सुरक्षा में हाईटैक उपकरण लगे हुए हैं और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को है, जो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है जिसकी गहन जांच की जानी चाहिए और यदि कोई खामियां हैं तो उन्हें तुरंत दूर किया जाना चाहिए। दूसरा, विपक्ष के 118 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वह भाजपानीत राजग का पक्ष लेते हैं और सत्र के दौरान विपक्षी सदस्यों को बोलने नहीं देते।

विपक्ष के गुस्से का कारण पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के बारे में राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति न देने को लेकर है। ध्रुवीकरण के इस वातावरण में अध्यक्ष और विपक्ष के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा था और संसद के शीतकालीन सत्र का यह टकराव और बढ़ गया जब 8 सांसदों को निलंबित किया गया और ऐसे ही आचरण के लिए भाजपा के सांसदों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि सरकार के पास संख्या बल है और लोक सभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास

प्रस्ताव जब 9 मार्च को बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा तो गिर जाएगा। बिरला ने नैतिकता का हवाला देते हुए निर्णय किया कि वे तब तक सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, जब तक उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हो जाता। इस स्थिति के लिए कौन दोषी है? भाजपा, जो संसद की कार्रवाई में व्यवधान को लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन का स्वरूप मानती है और अतीत में उसने कई बार ऐसा किया है या लोकसभा अध्यक्ष, जो ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के हितों की रक्षा करने के लिए उत्सुक हैं या इसका कारण लोकतंत्र का धीरे-धीरे क्षरण होना है, जहां एक ओर अच्छी चर्चाएं और बहस असंभव हो गई है। आज तक अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से लोक सभा के किसी भी अध्यक्ष को पद से नहीं हटाया नहीं गया।

लोकसभा अध्यक्ष का पद बहुत ही गरिमापूर्ण है और मूलतः वह सदन के सेवक हैं किंतु अब वह धीरे-धीरे उसके स्वामी बनते जा रहे हैं और इसका कारण प्रक्रिया के नियम हैं। इसके अलावा संसद में विधायी कार्य के संचालन के मानक गिर रहे हैं और इन नियमों को स्पष्टतः परिभाषित करने की आवश्यकता है। निःसंदेह अध्यक्ष का पद विरोधाभासी है। वह संसद या राज्य विधानसभा के पार्टी के टिकट पर लड़ता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष होकर कार्य करे, जबकि अगले चुनाव के लिए उसे उसी पार्टी से टिकट लेना पड़ता है। ऐसे में उसका निष्पक्ष होकर सदन की कार्रवाई चलाना शायद एक कठिन कार्य है। तीसरा, भाजपा के सांसद विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध एक प्रमाणिक प्रस्ताव लाए हैं, जिसमें उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाए और उन पर चुनाव लडने् के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि वह एक अर्बन नक्सल हैं और राष्ट्र विरोधी शक्तियों से मिले हुए हैं। इसके अलावा उनके सोरोस फाऊंडेशन, फोर्ड फाऊंडेशन, यू.एस. एड के साथ संबंध हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए उन्होंने अमरीका, थाइलैंड, कंबोडिया और वियतनाम की यात्रा की है।

इसके अलावा वे बड़ी चालाकी से लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, वह निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध अप्रमाणिक आरोप लगा रहे हैं और बिना किसी साक्ष्य के सरकार की गरिमा गिरा रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार इस प्रस्ताव को मतदान के स्तर तक ले जाने की अनुमति देगी? अतीत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब ऐसे प्रस्ताव मतदान के चरण तक नहीं पहुंचे। इसका संभावित परिणाम क्या होगा? यदि इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो यह संसद में एक राजनीतिक चर्चा होगी। अध्यक्ष निर्णय करेगा कि क्या किसी और कदम की आवश्यकता है? फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी को कानूनी रूप से तत्काल हटाया जाएगा या उन पर चुनाव लडने् से प्रतिबंध लगाया जाएगा। कुल मिलाकर अध्यक्ष सदन का, सदन के द्वारा और सदन के लिए होता है। उन्हें स्वयं को न्यायाधीश की भूमिका में रखना और पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए।

किसी विशेष विचार का पक्ष लेने या विरोध करने से बचना चाहिए, जिससे सदन के सभी वर्गों में उनकी सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता पर विश्वास बना रहे। सदन में इन तीन अनहोनी घटनाओं ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सौहार्द और विश्वास के टूटने का संकेत दे दिया है और दोनों पक्षों में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। अब इस स्थिति में दोनों पक्षों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि यहां से आगे कहां जा सकते हैं।

अब कड़वे फैसले ही गढ़ेंगे हिमाचल का भविष्य

डा. रचना गुप्ता

हिमाचल समेत 17 राज्यों में केंद्र सरकार की विशेष दरियादिली यानी राजस्व घाटा अनुदान (आर.डी.जी.) खत्म होने के बाद अब वक्त आ गया है, जब राज्य सरकारें आर.डी.जी. से आगे का सोचें, खासकर हिमाचल जैसा छोटा सा राज्य। वित्तीय नजाकत को समझते हुए वर्तमान कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही कुछ फैसलों के कड़वे घूंट पी लिए थे, ताकि खजाने में थोड़ा सुधार हो, लेकिन यही काम पूर्व में रही भाजपा या कांग्रेस सरकारों ने कर लिया होता तो इस बदहाली की नौबत न आती।

खैर, अब आर.डी.जी. बंद हो गई है, पिछली सरकारों द्वारा लिए गए कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ पार कर गया है, जिसका ब्याज चुकता करते-करते किसी भी दल की सरकार के पसीने छूटेंगे। दूसरे आर्थिक मुद्दे भी हैं जिन पर वर्तमान की कांग्रेस सरकार अंगारों पर चल रही है। इसलिए अब आर.डी.जी. से आगे कदम बढ़ाने व स्व-साधन विकसित करने का वक्त है और संकट की इस घड़ी में सरकारी कर्मियों को ही योद्धा बनकर चलना होगा ताकि गैर सरकारी जनता भी स्वयं को बेहतर स्थिति में ला सके। इसलिए मुफ्त की योजनाओं से इतर विकास के नए अवसरों को झटपट पाना और कठोर निर्णय लेना, वक्त की जरूरत बनी है। वरना राज्य का आगे चल पाना, यानी बुनियादी कामों का होना भी दुश्वार होगा।

बहरहाल सुधारों का पिटारा तत्काल प्रभाव से सुक्खू सरकार को शुरू करना चाहिए। इसमें पहल चुने हुए प्रतिनिधियो से ही करनी चाहिए, जिन्हें हर टर्म की अलग पैंशन मिलती है और कुछ-कुछ अंतराल के बाद वेतन-भत्ते भी बढ़ते रहते हैं। खासकर हर बार की चुनावी रिटर्न में कुछ की करोड़ों की भारी बढ़ौतरी देखी गई है। दूसरा, यदि पैंशन के मामले में देनदारी खासी बढ़ गई है, तो इस विषय में पुनर्विचार करना भी एक व्यावहारिक फैसला हो सकता है, क्योंकि पैंशन व एरियर से भी राज्य के खजाने को बहुत बड़ी मार मिल

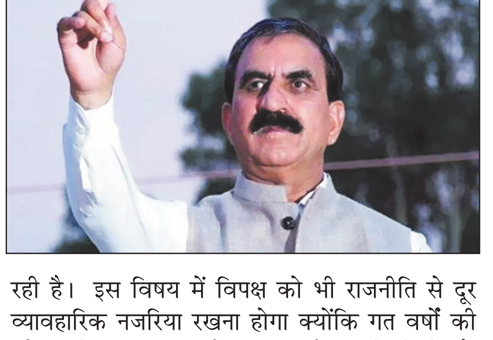

रही है। इस विषय में विपक्ष को भी राजनीति से दूर व्यावहारिक नजरिया रखना होगा क्योंकि गत वर्षों की प्रदेश की ऋण स्थिति, वेतन, एरियरों व डी.जी.पी. के साथ सभी सरकारों के निर्णय पर गौर करें तो कोई भी एक दल या पार्टी विशेष कटघरे में खड़ी नहीं होती बल्कि सभी होते हैं। क्योंकि गत ढाई दशकों में सबसिडी आधारित राजनीति सभी ने की। कर्ज सभी ने लिए। राजस्व सुधारों की कमी सभी स्तरों पर रही। वास्तव में हिमाचल बिना केंद्र की मदद के खुद तेजी से विकसित इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह पहाड़ी राज्य है।

प्रेम कुमार धूमल का 2 टर्म का कार्यकाल रहा। अब सभी मुख्यमंत्रियों का वर्ष 2000 से आगे के अनुमानित कर्ज आंकड़ों में अपने आप में काफी कुछ कहता है। प्रेम कुमार धूमल 14000 करोड़ रुपए का कर्ज, वीरभद्र सिंह के 2 कार्यकालों में 21500 करोड़ रुपए, जयराम ठाकुर के एक कार्यकाल में 22000 करोड़ रुपए (कोरोना काल) और सुखविंदर सिंह सुक्खू के 3 वर्ष के कार्यकाल में अनुमानित 18000 करोड़ रुपए (आपदा काल) ऋण लिया गया। इस तरह सुक्खू सरकार में, पिछली सरकारों का लिया हुआ कर्जा समेत मिलाकर करीब 1 लाख करोड़ आ गया। ऐसे में आर.डी.जी. का बंद होना भी वज्रपात ही है।

यह विडंबना है कि सभी को मालूम था कि हालात खराब हो रहे हैं। सी.ए.जी. ने भी स्पष्ट कर दिया था कि असंतुलन तेजी से हो रहा और आमदनी धीमी है। आयकर कम है, तब कर्ज लेना पड़ा। यानी खर्च बढ़ा, राजस्व नहीं। जो ऋण लिया वह सैलरी-पैंशन पर गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हुआ। हर सरकार के समय पर सबसिडी की मार प्रदेश को झेलनी पड़ी। प्रेम कुमार धूमल के समय 5वां, 6वां वेतन आयोग लागू किया। बिजली व किसानों की सबसिडी, नए मंडल, उपमंडल खोलना, कर्ज आधारित विकास मॉडल बना। वीरभद्र ने बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियां कर दीं। सामाजिक पैंशन विस्तार, बोर्ड निगम घाटे में। जयराम ठाकुर ने बिजली 125 यूनिट मुफ्त की, कोरोना काल में उधारी बढ़ी, राजस्व गिर गया, वेतन आयोग का एरियर मिलता रहा। सुक्खू सरकार में ओ.पी.एस. ने तगड़ा झटका दिया। कर्ज का ऋण देते रहे और दो बड़ी आपदाओं में पुनर्वास में भारी खर्च हुआ। ओ.पी.एस. इस समय ऋण क्षमता को 1800 करोड़ कम कर देता है क्योंकि यह डैडीकेटेड कॉरपस होता है। यही झटका इस सरकार को लगा।

वैसे चिंताजनक बात यह है कि प्रदेश की वृद्धि दर भी खास नहीं सुधर रही। वर्ष 2005-06 में यह 10 प्रतिशत थी जो 2011-12 में 7 प्रतिशत हो गई। 2018 में 6 प्रतिशत और 2019 में 4 प्रतिशत पर आ गई। आज प्रदेश की जी.डी.पी. हमारे देश की जी.डी.पी. से नीचे चल रही है। उधर दूसरी ओर 11वें वित्त आयोग ने प्रदेश को 4,549 करोड़ की अनुमानित घाटा भरपाई (आर.डी.जी.) दी, 12वें आयोग ने 10,202 करोड़, 13वें वित्तायोग ने 19300 करोड़, 14वें आयोग ने 40,624 करोड़, 15वें आयोग ने 4 वर्षों के (2024 तक) 37,199 करोड़ दिए हैं। इसमें सुक्खू सरकार के अब तक के सत्ता वर्ष शामिल हैं, जो करीब 17000 करोड़ बनते हैं। प्रदेश को 5 साल में अनुमानित 50000 करोड़ आर.डी.जी. मिलता था, वह अब बंद। यह बहुत बड़ी राहत हिमाचल जैसे राज्य के लिए थी। इस परिप्रेक्ष्य में अब हिमाचल को ठीक वैसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, जैसे भारत आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है। इसलिए सबसिडी व पैंशन को न्यौछावर करके हर हिमाचली को हाथ से हाथ मिलाकर चलना चाहिए। शुरुआत राजनीतिक दलों से की जानी चाहिए।

भारत के लिए बड़ा सबक है गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद

संतोष कुमार पाठक

20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 के लगभग वैश्विक एआई अग्रणी भारत की राजधानी दिल्ली में अपनी तरह के पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अपनी नई भूमिका की तलाश कर रहा भारत, दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवेंट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कर रहा है। यह पहली बार है जब एआई पर इस स्तर का वैश्विक सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने इसे लेकर दावा भी किया है कि इस शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख, मंत्रीगण, वैश्विक प्रौद्योगिकी अग्रणी, प्रख्यात शोधकर्ता, बहुपक्षीय संस्थान और उद्योग जगत के हितधारक एक साथ आएंगे और समावेशी विकास को बढ़ावा देने, सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत करने और सतत विकास को सक्षम बनाने में एआई की भूमिका पर विचार-विमर्श करेंगे। राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अभूतपूर्व वैश्विक भागीदारी के साथ चल रहा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अपने आप में यह बताता नजर आ रहा है कि भारत आज की तारीख में वैश्विक एआई संवाद का नेतृत्व कर रहा है और आने वाले दिनों में कोई भी देश भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्योंकि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वैश्विक एआई एजेंडा को आकार देने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। दुनियाभर के दिग्गजों के साथ-साथ इस समिट में भारत के भी कई विश्विद्यालय, कॉलेज और स्टार्टअप्स शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तो एआई को 5वीं औद्योगिक क्रांति की संज्ञा देते हुए यहां तक दावा किया कि, 3 लाख से ज़्यादा छात्रों और रिसर्चर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। देशभर के कई विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्टार्टअप ने समिट में एआई मॉडल्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। जाहिर सी बात है कि इस समिट के जरिए जहां चर्चा भारत के युवाओं की बौद्धिक क्षमता और टैलेंट की होनी चाहिए थी, वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मसार कर दिया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन में बने रोबोट को अपना इनोवेशन बताकर दिल्ली एआई समिट में पेश कर दिया। मीडिया से बात करते हुए एक प्रोफेसर ने बड़े ही गर्व के साथ चार पैरों वाले इस रोबोडॉग की खासियत भी कैमरे पर बताई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस प्रतिनिधि के हाव-भाव देखने लायक है। इसका नाम ओरियन बताते हुए उन्होंने दावा किया कि इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने तैयार किया है। सरकारी चैनल सहित देश के कई मीडिया संस्थानों ने इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जोर-शोर से चलाया और छापा भी। लेकिन चीन की तरफ से बयान आते ही पूरा मामला पलट गया। इसके बाद यह पता लगा कि वास्तव में यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं बल्कि चीन की एक कंपनी द्वारा बनाया गया एआई-पावर्ड रोबोटिक डॉग है, जो अपनी फुर्ती और एडवांस सेंसर्स के लिए दुनियाभर में मशहूर है। विवाद बढ़ने और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल होने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपने झूठ को स्वीकार कर लिया। यूनिवर्सिटी ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी कर यह स्वीकार किया कि यह रोबोडॉग उन्होंने नहीं बनाया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से झूठ का सहारा लेते हुए यह भी कह दिया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसे बनाने का दावा नहीं किया। जबकि उनके प्रोफेसर का वायरल वीडियो ही उनके झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। ऐसे में एक बार फिर से सरकार के विजन, नीति और फंड की व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार प्राइवेट विश्विद्यालय और कॉलेजों के सहारे देश में नई, बड़ी और स्पेशल रिसर्च नहीं करवा सकती क्योंकि इनकी भूमिका और इनके कामकाज का पूरा ढांचा ही संदिग्ध है।

इन देशों में सुरक्षा की नहीं होगी चिंता, बेफिक्र होकर बनाएं घूमने का प्लान

कई लोग विदेश घूमने की इच्छा रखते हैं। विदेश घूमने के लिहाज से अधिकतर देश शानदार हैं। हालांकि विदेशों की खूबसूरती किसी भी टूरिस्ट के मन को आसानी से भा सकती है। लेकिन जब भी विदेश घूमने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि क्या वह जगह सुरक्षा के लिहाज से सही है। क्योंकि सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायॉरिटी होती है। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आपको सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं कि वह कौन-कौन से देश हैं, जहां पर आप बेफिक्र होकर घूम सकते हैं।

आइसलैंड

आइसलैंड की आबादी 3,72,295 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार, यह दुनिया का सबसे सुरक्षित देश हैं। बता दें कि यहां पर क्राइम रेट काफी कम है। इसके साथ ही यह हाई-सिक्योरिटी वाला देश भी है। सभी तरह के अपराधों के प्रति यहां के नागरिकों का एक मजबूत सामाजिक दृष्टिकोण है। यह देश धार्मिक स्वतंत्रता देने के साथ ही महिलाओम और पुरुषों को समान अधिकार देता है। अगर आप भी विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आइसलैंड सुरक्षित देश है।

न्यूजीलैंड

आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की जनसंख्या 5,124,100 के आसपास है। यह देश भी घूमने और रहने के लिहाज से सुरक्षित है। यहां पर आप बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। न्यूजीलैंड का भी क्राइम रेट कम है। हालांकि साल 2019 में क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों पर हुए आतंकवादी हमले के कारण यहां का क्राइम स्कोर थोड़ा कम हो गया है। यह पर आप सुरक्षा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड में शांति वाले इलाके में पुलिस अपने पास हथियार भी नहीं रखती है।

पुर्तगाल

साल 2014 के अनुसार, पुर्तगाल दुनिया का 18वां सबसे सुरक्षित देश है। ऐसे में आप बिना सुरक्षा की चिंता किए बगैर यहां पर घूम सकते हैं। 10,270,865 के करीब आबादी वाला यह देश विभिन्न कारणों से सबसे सुरक्षित देशों में शीर्ष 5वां स्थान अर्जित किया है। बता दें कि आर्थिक विकास के कारण इस देश की बेरोजगारी दर 17 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक कम हो गई है।

आस्ट्रिया

26,177,413 के करीब जनसंख्या वाला देश आस्ट्रिया भी सुरक्षित देशों की गिनती में आता है। यहां पर भी अपराध दर काफी कम है। लेकिन यहां पर घूमने आने वाले टूरिस्टों और यहां पर रहने वाले स्थानीय निवासियों को जेबकतरों और पर्स-स्नैचर्स आदि घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप भी यहां पर घूमने आना चाहते हैं तो

आपको जेबकतरों से सावधान रहने की जरूरत होगी।

डेनमार्क

डेनमार्क 5,896,026 आबादी वाला देश है। बता दें कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार, यह दुनिया का 5वां सबसे सुरक्षित देश है। इस देश में अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और कम भ्रष्टाचार होने के साथ ही कुशल सुरक्षाबन मिलेगा। इसके अलावा यहां की हेल्थ सुविधाएं भी काफी बेहतर हैं। इस देश में लोग आरामदायक तरीके से अपनी जीवन व्यतीत करते हैं।

कनाडा

कनाडा की कुल आबादी 37,742,154 के करीब है। आबादी के लिहाज से कनाडा काफी छोटा देश है। यहां का अधिकतर हिस्सा बंजर जंगल है और यह बंजर जंगल हजारों मीलों तक फैला हुआ है। लेकिन घूमने के लिहाज से यह काफी सुरक्षित देश है। इस देश का अपराध दर भी काफी कम है।

सिंगापुर

सिंगापुर 59,43,546 के करीब आबादी वाला है। सिंगापुर में छोटी-मोटी चोरी और अन्य अपराधों के खिलाफ कुछ सख्त कानून हैं। जिसके कारण इसकी गिनती दुनिया के सुरक्षित देशों में होती है। हालांकि सिंगापुर को शहर-राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यह दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे सुरक्षित राज्य है।

जापान

जापान की जनसंख्या 125.93 मिलियन के आसपास है। सुरक्षा के लिहाज से यह सबसे सुरक्षित देश है। चीन और उत्तर कोरिया के करीब होने के बाद भी जापान एशियाई महाद्वीप का एक सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्थिर देश है। वैश्विक शांति सूचकांक में जापान हमेशा हाई स्कोर हासिल करता है।

चेक गणराज्य

चेक गणराज्य की आबादी 10,512,397 के करीब है। यहां पर हर वर्ष अपराध दर घटता प्रतीत होता है। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में चेक गणराज्य सुरक्षित देशों में से एक है। यहां पर आप सुरक्षा की परवाह किए बिना आराम से घूम-फिर सकते हैं।

स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड घूमने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट वहां पहुंचते हैं। बता दें कि यहां की आबादी 8.6 मिलियन के आसपास है। रहने और घूमने के लिहाज से यह देश सबसे ज्यादा बेस्ट है। फूड सिक्योरिटी के मामले में भी स्विट्जरलैंड दुनिया भर में चौथे स्थान पर है।

इन टिप्स को फॉलो कर हॉलिडे को बनाएं शानदार, ऐसे करें पैसों की बचत

कई लोगों को घूमना काफी पसंद होता है। कई बार लगातार ट्रैवल करने के बाद भी छकान नहीं होती है। लेकिन घूमने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। ऐसे में सेविंग्स का होना जरूरी होता है। घूमने के दौरान कई बार ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से घूमने की प्लानिंग करें तो आप पैसों की बचत कर सकते हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ट्रैवल के कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं। जिनकी मदद से आप ट्रैवल भी कर लेंगे और पैसों की सेविंग भी कर लेंगे।

हॉलिडे की योजना

अगर आप भी छुट्टी पर जाने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले यह डिसाइड करें की आप रिलैक्सिंग हॉलिडे के लिए समुद्र तट पर चाहते हैं या एडवेंचर्स करना चाहते हैं। जब आपको यह पता होता है कि आप घूमने के लिए कहां जाने वाले हैं तो वहां होने वाले खर्चे और यात्रा कार्यक्रम की योजना पहले से बना लें। इस दौरान आपके लिए रियलिस्टिक बजट बनाना आसान हो जाएगा।

रियलिस्टिक बजट

घूमने जाने की शुरूआत हॉलिडे रीयलिस्टिक बजट तय करने से शुरू होती है। आप कहीं भी घूमने जा रहे हों। कोई भी स्मार्ट ट्रैवलर यह बात काफी अच्छे से जानता है कि शानदार छुट्टियां बिताने के लिए एक रियलिस्टिक बजट की जरूरत होती है। जिसे आप आसानी से पहले ही बना सकते हैं।

ट्रैवल और खरीदारी

घूमने जाने के दौरान बुकिंग या खरीदारी पर कैशबैक कमा सकते हैं। इससे आपकी ट्रैवलिंग आसान हो जाती है। कई बार खरीददारी करने पर या बुकिंग करने के दौरान आपको कैशबैक मिलता है। इसलिए हमेशा इस ऑप्शन को ओपेन रखना चाहिए।

ऑफ सीजन में यात्रा

इस सीक्रेट को सभी स्मार्ट ट्रैवलर्स अपनाते हैं। अधिकतर ट्रैवल करने वाले ऑफ सीजन में यात्रा कर बड़ी बचत करते हैं। इस दौरान उनका ज्यादा खर्च नहीं होता है। क्योंकि वह ऑफ-पीक हॉलिडे सीजन में ट्रैवल करते हैं। ऑफ सीजन में ट्रैवल करने से फ्लाइट्स, होटल आदि सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं।

फ्लाइट्स चुनते समय फ्लेक्सिबल

पर्यटकों की आवाजाही सप्ताह के कुछ दिनों में कम होती है। इस समय यात्रा करने पर आपको सस्ती उड़ान भरने का मौका मिल सकता है। फ्लाइट की कीमत के आधार पर आप अपनी छुट्टियों को प्लान कर सकते हैं। इससे भी आप अच्छी खासी सेविंग कर लेंगे।

हॉस्पिटैलिटी कंपनी

आपको बता दें कि अपने नियमित ग्राहकों के लिए कई प्रमुख होटल चेंस और एयरलाइंस बहुत कम या बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के लॉयल्टी प्रोग्राम्स पेश करती हैं। इस दौरान आपको होटल चेंस और एयरलाइंस के जरिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड

क्रेडिट या डेबिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। यह पॉइंट अर्जित करने का एक क्विक और आसान तरीका है। जिसके बदले कई प्रमुख बैंक गिफ्ट्स और सर्विस के बदले में आपको रिवार्ड पॉइंट प्रदान करते हैं। जिन्हें किसी भी समय रिडीम किया जा सकता है।

सस्ता विकल्प खोजें

अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप उन विकल्पों को पता करें। जिनमें यात्रा सस्ती होने के साथ ही आने-जाने से लेकर रहने तक हर चीज के लिए काफी सारे विकल्प होते हैं। इस दौरान हॉलिडे प्लान करने के दौरान शानदार अनुभवों के लिए फ्लाइट्स के स्थान पर ट्रेनों की खोज करें।

सिक्किम घूमने का बना रहे हैं प्लान तो...

इन खूबसूरत जगहों को करें एक्सप्लोर, जन्नत में आने का होगा एहसास

देश की टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन्स में नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों का नाम गिना जाता है। नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप प्लान करने वाले अधिकतर लोग सिक्किम घूमना नहीं भूलते हैं। वैसे तो सिकिम्म में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं। ऐसे में अगर आप भी सिक्किम घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को एक्सप्लोर करना न भूलें। इन खूबसूरत जगहों पर घूमने के बाद आपका वापस आने का दिल नहीं करेगा। हिमालय की गोद में बसा सिक्किम भले ही एक छोटा सा राज्य है। लेकिन यहां की खूबसूरत वादियों से लेकर नेचर की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको सिक्किम की कुछ शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में...

त्सोमगो झील की सैर

अगर आप सिक्किम में किसी रोमांटिक जगह पर घूमना चाहते हैं तो त्सोमगो लेक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। त्सोमगो लेक सिक्किम की राजधानी गंगटोक से महज 40 किलोमीटर दूर है। यह लेक 12,400 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस लेक को चांगु झील के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि सर्दियों में यह लेक पूरी तरह से जम जाती है। वहीं बसंत ऋतु के मौके पर इस लेक की सुंदरता कई खूबसूरत फूलों से खिल उठती है।

जुलुक का दीदार

जुलुक का दीदार करने के लिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 3 घंटे का सफर तय करना होता है। इस दौरान रास्ते में 32 हेयरपिन मोड़ आपकी यात्रा को अधिक शानदार बना सकते हैं। वैसे तो जुलुक सिक्किम का एक छोटा सा और काफी खूबसूरत गांव है। लेकिन यहां से 11 फीट की ऊंचाई पर स्थित थुंबी व्यू प्वाइंट कंचनजंघा चोटी अपने खूबसूरत नजारों के लिए फेमस है। जुलुक की ट्रिप के दौरान कपुप लेक या हाथी झील का भी दीदार कर सकते हैं।

पेलिंग की ट्रिप

गंगटोक से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पेलिंग भी घूमने के लिए बेस्ट जगह है। यह जगह रोमांच के लिए फेमस है। पेलिंग का सफर एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट हो सकता है। यहां पर एडवेंचर के शौकीन लोग रॉक क्लाइंबिग, ट्रेकिंग, कयाकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रिवर राफ्टिंग जैसी कई एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा सांगचोएलिंग मठ रिम्बी वॉटरफॉल स्काई वॉक और सेवारो रॉक गार्डन का दीदार कर अपने सफर को शानदार और रोमांचक बना सकते हैं।

रंवगला

रंवगला सिक्किम का खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय पर्वतों से घिरा रंवगला मैनम और तेंडोंग हिल्स टॉप पर मौजूद है। बता दें कि रंवगला गंगटोक से लगभग 63 किलोमीटर की दूर स्थित है। नेचर लवर्स के लिए रंवगला की सैर बेस्ट हो सकती है। यहां से आप ग्रेटर हिमालय के मनमोहक नजारों को बेहद नजदीक से देख सकते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

यूपी के दोनों डिप्टी सीएम से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत

लखनऊ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक से मुलाकात की। इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। हालांकि, प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में फेरबदल की चर्चाओं के बीच सीएम व डिप्टी सीएम से संघ प्रमुख की मुलाकात ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। संघ प्रमुख ने दोनों डिप्टी सीएम से बृहस्पतिवार सुबह करीब 10-10 मिनट के लिए मुलाकात की। इसके पहले, मुख्यमंत्री बुधवार को रात आठ बजे संघ प्रमुख से मिले राजधानी के निराला नगर स्थित संघ कार्यालय परिसर में सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचे। एकांत में दोनों के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई। संघ प्रमुख दो दिवसीय प्रवास पर राजधानी लखनऊ में थे और बुधवार को उनके प्रवास का अंतिम दिन था।

पीएम मोदी सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील हैं : ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संत रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर उनके नाम के कथित दुरुपयोग को लेकर तीखा प्रहार किया। फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से बनर्जी ने प्रधानमंत्री को सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील बताया। एक बार फिर स्तब्ध! हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बंगाल की महान हस्तियों के प्रति अपनी सांस्कृतिक असंवेदनशीलता का आक्रामक प्रदर्शन किया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा आज युगावतार (हमारे युग में ईश्वर का अवतार) श्री श्री रामकृष्ण परमहंसदेव की जन्मतिथि है। इस अवसर पर महान संत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हमारे प्रधानमंत्री ने उनके नाम के आगे अभूतपूर्व और अनुचित उपसर्ग स्वामी जोड़ दिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के प्रसिद्ध संत रामकृष्ण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

बेंगलुरु कचरा विवाद पर डीके को मिला विधायक का साथ

बेंगलुरु। कांग्रेस विधायक पीएम नरेंद्रस्वामी ने गुरुवार को बेंगलुरु के डंप यार्ड मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान का समर्थन किया और भाजपा की आलोचनाओं का सामना कर रहे कर्नाटक के मंत्रियों के हालिया विवादास्पद बयानों का बचाव किया। मीडिया से बात करते हुए, नरेंद्रस्वामी ने बेंगलुरु के डंप यार्ड विवाद पर अपनी राय रखी, जहां भाजपा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने कचरा प्रबंधन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है और भाजपा नेताओं के घरों के सामने कचरा फेंकने के बारे में डीके शिवकुमार के बयान की आलोचना की है। कांग्रेस विधायक ने स्पष्ट किया कि बेंगलुरु में कचरा प्रबंधन किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं बल्कि ग्रेटर बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (जीबीए) के तहत एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर विधायक असहयोग करते हैं, तो हम जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मांगा केंद्र से स्पेशल सपोर्ट

रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के भाषण के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया और इसे एक नवजात शिशु बताया जिसे विकास के लिए पोषण और समर्थन की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के लोगों के सामने मौजूद चुनौतियों के समाधान में भारत सरकार की सहायक भूमिका निभाने की उन्हें पूरी उम्मीद है। हेमंत सोरेन ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि हमारा राज्य गरीब और पिछड़ा हुआ है। यह एक नया राज्य है और इसे एक नवजात शिशु की देखभाल करनी है। ऐसे में भारत सरकार से हमारी भी अपेक्षाएं हैं। हम अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे। कई ज़रूरतें हैं, कई चुनौतियां हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को कहीं न कहीं बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए विशेष ध्यान देना चाहिए।

ब्लैक बॉक्स के नष्ट होने पर जय पवार ने उठाए सवाल

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे जय पवार ने अपने पिता से जुड़े हालिया विमान हादसे पर गंभीर चिंता जताई है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक संदेश में जय पवार ने कहा कि विमान के ब्लैक बॉक्स का इतनी आसानी से नष्ट होना असंभव है और उन्होंने घटना की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की। जय पवार ने लिखा कि महाराष्ट्र के लोगों को इस दुखद दुर्घटना के बारे में संपूर्ण, पारदर्शी और निर्विवाद सत्य जानने का अधिकार है। उन्होंने मांग की कि एयरलाइन की उड़ानें तत्काल निलंबित की जाएं और विमान रखरखाव में संभावित गंभीर अनियमितताओं की गहन जांच की जाए। उन्होंने आगे कहा कि यदि जांच के दौरान कोई लापरवाही या कदाचार पाया जाता है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के विमान दुर्घटना को लेकर रोहित पवार के दावों का समर्थन किया है।

असम चुनाव से पहले भाजपा का हुंकार

कांग्रेस को जड़ से उखाड़ देंगे :नितिन नबीन

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरुवार को असम को कांग्रेस-मुक्त बनाने के पार्टी के संकल्प को दोहराते हुए कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों से पहले जमीनी स्तर पर प्रयास तेज करने का आग्रह किया। बूथ समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से असम के विकास में पूर्ण सहयोग देने का आह्वान किया। नबीन ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और ऊपरी असम क्षेत्र की सभी 26 सीटों पर जीत हासिल करेगी।

उन्होंने कहा कि हमें असम के विकास में पूर्ण सहयोग देना होगा। हमें हर बूथ पर पूरी ताकत और समर्पण के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमें 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। मुझे विश्वास है कि भाजपा डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और ऊपरी असम क्षेत्र की सभी 26 सीटों पर जीत हासिल करेगी। हमें असम को कांग्रेस-मुक्त बनाना है। एएनआई से बात करते हुए नबीन ने असम में शुरू की गई विकास पहलों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए लगातार प्रगति कर रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम के लोगों को विभिन्न विकास योजनाओं से प्रभावी ढंग से जोड़ा गया है। उन्होंने एएनआई को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जिस तरह से यहां के लोगों को विकास योजनाओं से जोड़ा है, उससे विरासत के साथ विकास का संकल्प साकार हुआ है। आज मुझे यहां की सांस्कृतिक विरासत को देखने का अवसर भी मिला।

नबीन ने आगे कहा कि असम पूरी तरह सुरक्षित है और एक विकसित राज्य बनने की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि असम पूरी तरह सुरक्षित होते हुए भी विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि यहां भाजपा-एनडीए की भारी बहुमत वाली सरकार बनेगी। इससे पहले दिन में, नबीन ने केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल, असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया और अन्य लोगों के साथ तिनसुकिया के बोर नामघर में पारंपरिक वेशभूषा में पूजा-अर्चना की। असम में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा कांग्रेस के खिलाफ अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस का मिशन असम

मां कामाख्या की शरण में प्रियंका गांधी

गुवाहाटी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और गौरव गोगोई ने गुरुवार को गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना की। प्रियंका गांधी वाड्रा, जो दिन में पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुकी थीं, ने मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि मैंने मां कामाख्या का आशीर्वाद लिया और मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी इस दौरान मौजूद रहे।

बैठक के दौरान नेताओं ने चुनाव परिणामों पर विस्तार से चर्चा की। प्रियंका गांधी ने नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत पर खुशी व्यक्त की और पार्टी के प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री रेड्डी को बधाई दी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि निर्णायक परिणाम राज्य सरकार द्वारा कल्याण और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन से जनता की संतुष्टि को दर्शाता है। ङ्ग पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि आज दिल्ली में मेरी मुलाकात एआईसीसी की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी से हुई। हमने राज्य में नगर निगम चुनावों के परिणामों पर चर्चा की। श्रीमती प्रियंका गांधी ने नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत पर खुशी व्यक्त की और उन्हें बधाई दी। मैंने उनसे कहा कि जनता राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित कल्याण और विकास कार्यक्रमों से संतुष्ट है, यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई है।

तेलंगाना में हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश दिया है, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कई नगरपालिकाओं और नगर निगमों में शानदार प्रदर्शन किया है। इन परिणामों को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा अपनाई गई शासन शैली का समर्थन माना जा रहा है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में। कई शहरी स्थानीय निकायों में हुए इन चुनावों में मतदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जो नागरिकों की बढ़ती सहभागिता को दर्शाती है। मतगणना के रुझान और शुरुआती परिणामों से संकेत मिलता है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में वार्डों में बढ़त हासिल की है, जबकि विपक्षी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में कड़ी टक्कर दी है।

विशाखापत्तनम में भारत का शक्ति प्रदर्शन

नईदिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मिलान-2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया, जो इस प्रमुख बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास की शुरुआत का प्रतीक है। उद्घाटन के दौरान, रक्षा मंत्री ने 74 देशों के विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मिलान 2026 अब तक का सबसे बड़ा और सबसे समावेशी संस्करण है। उन्होंने कहा कि यह संस्करण भारत को एक विश्वसनीय और जिम्मेदार समुद्री साझेदार के रूप में वैश्विक समुद्री समुदाय के भरोसे को दर्शाता है।

सिंह ने कहा कि इस वर्ष, 74 देशों की भागीदारी के साथ, मिलान 2026 अब तक का सबसे बड़ा और सबसे समावेशी संस्करण है, जो भारत को एक विश्वसनीय और जिम्मेदार

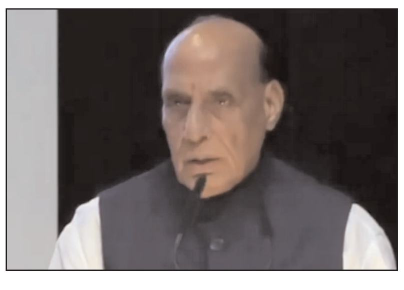

समुद्री साझेदार के रूप में वैश्विक समुद्री समुदाय के भरोसे का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने आगे बताया कि यह प्रमुख बहुपक्षीय मंच भागीदार देशों के बीच अंतर-संचालनीयता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि पेशेवर अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके, इस अभ्यास का उद्देश्य दक्षता में सुधार करना और पारस्परिक लाभ पर आधारित संबंधों के विकास के माध्यम से भागीदार नौसेनाओं के बीच मित्रता को गहरा करना है।

सिंह ने कहा कि मिलान 2026 का उद्देश्य भागीदार देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता को बढ़ाना, पेशेवर अनुभवों और प्रथाओं को साझा करके पेशेवर दक्षता में सुधार करना और पारस्परिक लाभ के संबंधों के विकास के माध्यम से भागीदार नौसेनाओं के बीच मित्रता को गहरा करना है। सभा को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि मिलान का दायरा और प्रतिष्ठा दोनों में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी भागीदारों के संयुक्त प्रयासों से, यह आयोजन एक क्षेत्रीय समन्वय से विकसित होकर दुनिया के सबसे प्रमुख बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यासों में से एक बन गया है।

बिना इजाजत देश नहीं छोड़ूंगा: अनिल अंबानी

नईदिल्ली। अनिल अंबानी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि संबंधित कंपनियों में उनकी भूमिका केवल गैर-कार्यकारी निदेशक की थी और वे इन कंपनियों के दैनिक प्रबंधन या परिचालन मामलों में शामिल नहीं थे। यह बयान अनिल डी अंबानी की ओर से ईएएस सरमा बनाम भारत संघ एवं अन्य नामक जनहित याचिका में दायर किए गए शपथपत्र/अनुपालन हलफनामे में दिया गया है। इस याचिका में अनिल अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े 1.5 लाख करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। हलफनामे में अंबानी ने कहा है कि वे मामले के तथ्यों से पूरी तरह अवगत हैं और शपथ लेने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने कहा है कि न्यायिक अभिलेख में स्पष्टता, पूर्णता और प्रक्रियात्मक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह हलफनामा दायर किया जा रहा है ताकि न्यायालय को व्यापक तथ्यात्मक परिदृश्य की जानकारी रहे। सर्वोच्च न्यायालय के 4 फरवरी, 2026 के आदेश का हवाला देते हुए, उन्होंने न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए इस वचन को दोहराया है कि वे पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। इस हलफनामे के माध्यम से उन्होंने औपचारिक रूप से इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर दर्ज कराया है।

खेल
प्रमुख समाचार

सुपर 8 से पहले टीम इंडिया के लिए दो बड़ी चिंताएं

अहमदाबाद। भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डोएशे ने इस बात पर सहमति जताई कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों वाले शीर्ष क्रम के लिए विपक्षी टीमों का सही रणनीति बनाना और फिंगर (उंगलियों के) स्पिनरों के खिलाफ बल्लेबाजों का संघर्ष टी20 विश्व कप के सुपर आठ में भारत के सामने दो अहम मुद्दे होंगे। डोएशे ने नीदरलैंड के खिलाफ अंतिम लीग मैच में भारत की जीत के बाद पत्रकारों से कहा कि खिताब के प्रबल दावेदार ने अभी तक एक भी मैच ऐसा नहीं खेला है जिसमें उसका पूरी तरह से दबदबा रहा हो।

भारत के शीर्ष तीन बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और तिलक वर्मा शामिल हैं। यह तीनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और डोएशे ने स्वीकार किया कि इससे विपक्षी टीमों के लिए उनके खिलाफ रणनीति बनाना आसान हो गया है। प्रतिद्वंद्वी टीमें अभिषेक शर्मा सहित शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने के लिए पावरप्ले में ऑफ स्पिनरों का इस्तेमाल कर रही हैं। अभिषेक इस टूर्नामेंट में तीन मैच में खाता भी नहीं खोल पाए हैं जबकि कुछ समय पहले तक वह अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे। नीदरलैंड के ऑफ स्पिनर आर्यन दत्त ने बुधवार को पावरप्ले में तीन ओवर फेंके और अभिषेक और किशन को आउट किया। डोएशे का मानना है कि भारत को उंगलियों से गेंदबाजी करने वाले स्पिनरों के खिलाफ अपने खेल में बड़े सुधार की जरूरत है। घरेलू टीम को दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर आठ मैचों में उंगलियों से गेंदबाजी करने वाले स्पिनरों से निपटने का तरीका ढूंढना होगा। भारत रविवार को यहां सुपर 8 के अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। डोएशे ने कहा, मुझे लगता है कि बेहतर विकेटों पर आपको ऐसा (स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजों को संघर्ष करते हुए) देखने को नहीं मिलेगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 1236 अंक का लगाया गोता, निफ्टी 25,454 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में तेजी के बावजूद भारतीय शेयर बाजार गुरुवार (19 फरवरी) को सपाट शुरुआत के बाद बड़ी गिरावट में बंद हुए। भूराजनीतिक चिंताओं के कारण निवेशकों के सेंटीमेंट्स पर नेगेटिव असर पड़ने से बाजार में दो सप्ताह से अधिक समय में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स मजबूती के साथ 83,979 अंक पर खुला। लेकिन खुलने के कुछ देर में ही बढ़त गंवा दी। दोपहर के कारोबार में गिरावट बढ़ गई। अंत में यह 1236.11 अंक या 1.48 प्रतिशत की गिरावट लेकर 82,498.14 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी मजबूती के साथ 25,873 पर खुला लेकिन कुछ ही देर में सपाट स्तर पर आ गया। बाद में बिकवाली हावी हो गई। अंत में 365 अंक या 1.41 फीसदी की गिरावट के साथ 25,454.35 पर बंद हुआ।

एआई के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश करेंगे मुकेश अंबानी

नई दिल्ली। एआई इंपैक्ट समिट में भारत के अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी बड़े एलान किए। उन्होंने कहा कि एआई का सबसे अच्छा दौर आना अभी बाकी है। एआई कई क्षेत्रों में नए दौर की शुरुआत कर सकता है। मौजूदा दौर में कृत्रिम बुद्धिमता के असर को रेखांकित करते हुए कहा, आज एआई को लेकर दुनिया दोराहे पर खड़ी है। एक रास्ता कम, महंगे एआई और कंट्रोल्ड डाटा की तरफ ले जाता है, दूसरा सस्ता, आसानी से मिलने वाली एआई की सुविधा सुनिश्चित करता है। मुकेश अंबानी ने अपने घराने की प्रतिबद्धता साझा करते हुए कहा, जिस तरह कंपनी ने मोबाइल डाटा का कॉस्ट कम किया है, उनका ग्रुप एआई की कॉस्ट भी कम करेगा। उन्होंने कहा कि जियो और रिलायंस इंडिया लिमिटेड भारत में एआई के लिए अगले सात वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगी।

आईटी सेक्टर में विदेशी निवेशकों की बड़ी बिकवाली

नईदिल्ली। भारतीय आईटी सेक्टर में विदेशी निवेशकों का भरोसा डगमगाता दिख रहा है। फरवरी के पहले 15 दिनों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने आईटी शेयरों में जमकर बिकवाली की है। डिपॉजिटरी आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में करीब 10,956 करोड़ रुपए की निकासी हुई है, जिससे सेक्टर में विदेशी होल्डिंग चार साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार, आईटी कंपनियों में FIIs की कुल हिस्सेदारी घटकर 4.49 लाख करोड़ रुपए रह गई है। जनवरी 2026 के अंत में यह आंकड़ा 5.34 लाख करोड़ रुपए था यानी महज दो हफ्तों में करीब 16 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। गौरतलब है कि 2025 की शुरुआत में यह निवेश 7.3 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर था। मौजूदा गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है बिकवाली की एक बड़ी वजह 'जेनरेटिव एआई' को लेकर बढ़ती आशंकाएं हैं।

टाटा ग्रुप और ओपनएआई बनाएंगे एआई डेटा सेंटर

नईदिल्ली। टाटा ग्रुप, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और ओपनएआई ने एंटरप्राइज, कंज्यूमर और सामाजिक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित इनोवेशन को बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। टाटा ग्रुप भारत का पहला बड़े पैमाने का ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर बनाएगा, जो अगली पीढ़ी के एआई ट्रेनिंग और इंफरेंस (एआई से रिजल्ट निकालने) के लिए खास तौर पर तैयार किया जाएगा। ग्रुप ने कहा कि वह ओपनएआई के साथ मिलकर भारत का पहला 100 मेगावॉट क्षमता वाला डेटा सेंटर बनाएगा, जिसे बाद में बढ़ाकर 1 गीगावॉट तक किया जाएगा। यह साझेदारी कई क्षेत्रों में होगी। इसमें टाटा ग्रुप की कंपनियों में एआई आधारित इनोवेशन को बढ़ावा देना शामिल है।

युवाओं व नारी सशक्तीकरण को समर्पित है यूपी बजट

मृत्युंजय दीक्षित

विगत कुछ माह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसमुदाय को सरकार के निर्णयों से अवगत कराने के लिए पाती लिखने का अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। इस बार बजट के बाद लिखी अपनी पाती में उन्होंने उत्तर प्रदेश के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की विशेषताओ पर प्रकाश डाला है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि यह बजट युवाओं व नारी शक्ति के लिए एक ऐतिहासिक बजट है। उत्तर प्रदेश का यह बजट नवाचार का बजट है। नवनिर्माण के 9 वर्षों की यह यात्रा प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

मुख्यमत्री योगी पूर्व में भी कह चुके हैं कि विगत नौ वर्षों में यूपी असीमित क्षमताओं वाला प्रदेश बन चुका है।इस बजट में युवाओं को रोजगार उपलबध कराने के लिए एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमों को विकसित करते हुए वृहद निवेश की नई योजनाओं को प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है। उभरती हुई नयी तकनीकीकी कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। प्रदेश में पहली बार स्टेट डेटा अथारिटी का गठन करने की ऐतिहासिक पहल की गई है। यह प्रदेश में वास्तविक समय पर आंकड़ों के संग्रह और इसके अनुश्रवण के साथ भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश एआई मिशन, एआई डेटा लैब, एआई सेंटरऑफ एक्सीलेंस तथा डेटा सेंटर क्लस्टर प्रदेश को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एआइ एवं डीप टेक के क्षेत्र में एक एक नए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होंगे। बजट के अनुसार टेक युवा समर्थ युवा卐 योजना के अंतर्गत 25 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।

बजट में एआई को प्राथमिकता दी गई है

जिसके लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत प्रदेश की 49 आईटीआई में एआइ लैब स्थापित की जाएगी। एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एआई ठेटा लैब की स्थापना के लिए 32.32 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। साइबर सुरक्षा को भी बजट में अहम स्थान मिला हे। प्रदेश में पहली बार स्टार्ट अप इन्क्यूबेटर हब बनने जा रहा है इस कार्य के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यू -हब का मुख्यालय लखनऊ और दूसरा इन्क्यूबेटर गौतमबुद्धनगर में बनाया जाएगा। यू -हब से ऐसे स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा ।राजधानी के परिषदीय विद्यालयों को एआई से जोड़ा जाएगा। स्मार्ट कक्षाओं में छात्रों को परंपरागत के साथ आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा मिलेगी।

युवाओ के लिए रोजगार के नए क्षेत्रो का सृजन किया जा रहा है। हथकरघा, पावरलूम और गारमेंटिंग सेक्टर में रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया है। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 30 हजार रोजागर सृजन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 -27 में 800 इकाइयों की स्थापना कर 16हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत उत्पादन के लिए 10 करोड़ और खजनी गोरखपुर स्थित कम्बल उत्पादन केंद्र के आधुनिकीकरण के लिए भी पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है।

युवाओ के लिए पर्यटन के माध्यम से भी रोजगार सृजन करने की व्यवस्था बजट में की गई है । इसके लिए युवा पर्यटन क्लब बनाए जाएंगे। युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। गोरखपुर में स्टेट इंस्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी और फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट अलीगढ़ को उच्चीकृत कर स्टेट इंस्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बनाया जाएगा। वहीं युवा पर्यटन क्लबॉन के लिए तीन करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत नि:शुल्क कोचिंग व्यवस्था तथा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम से युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। बजट मे एमएसएमई सेक्टर को पर्याप्त धन मिलने से लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम को बढ़ावा मिलने से युवाओ के लिए रोजगार और नौकरी के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

एआई से रोजगार बढ़ने की काफ़ी संभावना है: संजय

रायपुर। नई दिल्ली में ए आई इंपैक्ट समिट में छत्तीसगढ़ के युवाओं के द्वारा उल्लेखनीय प्रदर्शन किए जाने की नागरिक आपूर्ति निगम छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने प्रशंसा करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी क्षेत्र में टैलेंट की कमी नहीं है। यहां के युवा शिक्षा,कला इत्यादि क्षेत्रों में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं. उन्होंने प्रदेश के युवाओ को इस क्षेत्र में आगे बढ़कर नया कुछ करने का आह्वान करते हुए कहा कि ए आई तकनीक से राज्य में रोजगार के

अवसर बढ़ने की काफ़ी संभावना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान और चिकित्सा क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है. उल्लेखनीय है कि एआई इंपैक्ट समिट में छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली अनुराग मानिक और आस्था मानिक ने कर्तव्य एप्प प्रस्तुत किया जोकि ए आई जनित आवाज और वास्तविक आवाज को अलग-अलग पहचान लेने में सक्षम है.अध्यक्षसंजय श्रीवास्तव ने उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन युवाओ नेइस प्रतियोगिता में हजारों टैलेंटेड प्रतिभागियों के बीच कई कठिन चरणों कोसफलतापूर्वक पार करते हुए शीर्ष स्थान हासिल करने में सफलता पाई है।

छत्रपति शिवाजी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत: मुख्यमंत्री

महानाट्य 'जाणता राजा' के माध्यम से जीवंत हुई शिवाजी महाराज की गौरवगाथा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन साहस, धैर्य, रणनीति और आदर्श नेतृत्व का प्रेरक उदाहरण है, इसलिए हम सभी को अपने जीवन में शिवाजी जैसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में भी अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। अफजल खाँ के साथ हुई घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी ने संकट को भांपकर धैर्य और रणनीति से निर्णय लिया और विजय प्राप्त की। इसी प्रकार शाइस्ता खान के विरुद्ध उनकी युक्तिपूर्ण रणनीति यह सिखाती है कि बड़े से बड़े शत्रु को भी सूझबूझ और साहस से पराजित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने साइंस कॉलेज मैदान पहुंचकर ऐतिहासिक महानाट्य 'जाणता राजा' के मंचन के दौरान संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिवाजी महाराज केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि उच्च आदर्शों वाले शासक भी थे। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों की आस्था का सम्मान किया और महिलाओं के सम्मान को

सर्वोच्च प्राथमिकता दी। माता जीजाबाई के संस्कारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का चरित्र हमें मर्यादा, नैतिकता और सम्मानजनक आचरण का संदेश देता है।

मुख्यमंत्री साय ने अपने छात्र जीवन की स्मृतियों को साझा करते हुए महाकवि भूषण की पंक्तियों का उल्लेख किया, जिनमें शिवाजी महाराज के पराक्रम और वीरता का अद्भुत वर्णन मिलता है। उन्होंने कहा कि शिवाजी का जीवन केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है।

राजधानी रायपुर में प्रारंभ हुआ ऐतिहासिक महानाट्य 'जाणता राजा' का यह विशेष मंचन 22 फरवरी तक प्रतिदिन शाम को साइंस कॉलेज मैदान में प्रस्तुत किया जाएगा। लगभग तीन घंटे की यह भव्य प्रस्तुति छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की गाथा पर आधारित है, जिसमें सजीव दृश्य, विशाल मंच सज्जा और तकनीकी उत्कृष्टता के माध्यम से दर्शकों को ऐतिहासिक काल का जीवंत अनुभव कराया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के तत्वाधान में आयोजित इस महानाट्य के लिए महाराष्ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर सभागृह में ऑडिशन आयोजित किए गए थे, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लगभग 40 स्थानीय कलाकारों का चयन किया गया। चयनित कलाकारों ने निर्देशक योगेश शिरोले के मार्गदर्शन में गहन अभ्यास किया। स्थानीय कलाकारों में प्रांजल बक्षी, वर्तिका क्षीरसागर, कृति लाड, आकांक्षा और आस्था काले सहित अन्य प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। मंचन के दौरान घोड़ों के साथ सैनिकों की टुकड़ी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही, वहीं ऊंटों को भी प्रस्तुति में शामिल किया गया।

भाजपा के जिला सोशल मीडिया एवं आईटी सेल की संयुक्त बैठक संपन्न

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया एवं आईटी सेल की संयुक्त बैठक आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को भाजपा जिला कार्यालय, एकात्म परिसर रायपुर में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी मिथुल कोठारी, प्रदेश आईटी सेल संयोजक सुनील पिल्लई एवं जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी मिथुल कोठारी ने वर्तमान समय में सोशल मीडिया के साथ एआई की उपयोगिता पर विशेष जोर देते हुए विपक्ष द्वारा चलाए जा रहे भ्रामक प्रचार एवं फॉल्स नैरेटिव का तथ्यात्मक जवाब देने की बात कही। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक सुझाव दिए। प्रदेश आईटी सेल संयोजक सुनील पिल्लई ने आईटी सेल की कार्यप्रणाली, सरल पोर्टल के उपयोग तथा वर्तमान समय में डाटा मैनेजमेंट की महत्ता पर महत्वपूर्ण टिप्स प्रदान किए। जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने आईटी सेल एवं सोशल मीडिया की टीम का गठन शक्ति केंद्रों तक करने तथा उसके सक्रिय संचालन के निर्देश मंडल एवं मोर्चा अध्यक्षों को दिए।

बैठक में जिला महामंत्री गुंजन प्रजापति, सुरेश पटेल, चंद्र विशाल भूरा, सदाशिव सोनी, तोषण कुमार साहू, कृतिका जैन, ओमप्रकाश साहू, अखिलेश कश्यप, पंकज जगत, अर्पित सूर्यवंशी, राम प्रजापति, संदीप जंघेल, सुनील कुकरेजा, सचिन सिंघल, भीमवंत निषाद, विशेष शाह, अभिषेक तिवारी सहित मंडल के आईटी सेल एवं सोशल मीडिया पदाधिकारी उपस्थित रहे।

पीएम आवास योजना परिसरों में घूमेंगे अब निगम के अधिकारी

रहवासियों से लेंगे मौलिक समस्याओं की प्रत्यक्ष जानकारी -मीनल

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन की नगर निगम प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा के सम्बंधित अधिकारीगण रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना आवासीय परिसरो में घूमेंगे एवं वहाँ के रहवासियों से मिलकर उनसे आवासीय परिसर में मौलिक समस्याओ एवं सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करने प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे। किसी भी मौलिक सुविधा जैसे सफाई, पानी, प्रकाश व्यवस्था आदि में कोई भी कमी किसी भी प्रधानमंत्री आवास योजना परिसर में मिलने पर तत्काल अधिकारीगण संबंधित जोन क्षेत्र के जोन कमिश्नर एवं संबंधित जोन अधिकारियों को इससे तत्काल अवगत कराकर उन्हें शीघ्र निराकरण करवाने हेतु कहेंगे। जोन कार्यालय के संबंधित अधिकारी तत्काल संबंधित आवासीय परिसर क्षेत्र स्थल पहुंचकर रहवासियों से मिलेंगे और जनसमस्याओं की प्रत्यक्ष जानकारी लेकर उनका यथासंभव शीघ्र निराकरण करवाने का कार्य प्राथमिकता के साथ करायेंगे। उक्ताशय के निर्देश नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने निगम मुख्यालय प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा के अधिकारियों एवं जोन अधिकारियों को दिये। महापौर ने प्रधानमंत्री आवास योजना परिसरों के रहवासियों की मौलिक समस्याओं की जानकारी लेकर उनका जोन के माध्यम से शीघ्र त्वरित निराकरण हेतु सकारात्मक पहल की है ।

कांग्रेस ने गरीबों की छत छीनकर अपनी जेबें भरने का काम किया : अमित चिमनानी

रायपुर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए यह सवाल दागा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना में किए गए घोटालों को लेकर कैग की रिपोर्ट में उठाए गए गंभीर सवालों पर कांग्रेस का कोई भी नेता बोलने को तैयार क्यों नहीं है? श्री चिमनानी ने कांग्रेस पर यह भी सवाल दागा कि गरीबों के आवास को छीनकर जो भ्रष्टाचार किया गया, उसका पैसा क्या केवल राज्य के नेताओं ने ही आपस में

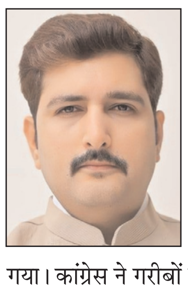

बाँटा है या यह पैसा राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक भी पहुँचा है?

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता चिमनानी ने कांग्रेस के शासनकाल को घोटालों का काल बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने न केवल धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि गरीबों के सिर से छत छीनने का पाप भी किया है। कांग्रेस के कार्यकाल में जहाँ भगवान शंकर और गौ माता के नाम पर बड़े-बड़े घोटाले हुए, वहीं गरीबों के आशियानों को भी नहीं बख्शा गया। कांग्रेस ने गरीबों की छत छीनकर अपनी जेबें भरने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस प्रकार की अनियमितताएं सामने आई हैं, वह कांग्रेस के असली चेहरे को उजागर करती हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री चिमनानी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार के कई गंभीर मुद्दे उठाए और कहा कि ऐसे लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम पर आवास योजना की राशि निकाल ली गई। जिन लोगों के पास जमीन का कोई टुकड़ा नहीं था, उनके नाम पर भी सरकारी खजाने से पैसे जारी किए गए। पहली किस्त मिलने के बाद, किसी दूसरे पूर्ण निर्मित मकान की फर्जी तस्वीरें दिखाकर पूरी राशि हड़प ली गई।

भूपेश की अमर्यादित टिप्पणी पर पलटवार

अब तो बघेल ओछी राजनीति छोड़कर मर्यादा का पालन करना सीखें : नलिनीश ठोकने

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई अनर्गल टिप्पणी पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। श्री ठोकने ने कहा कि सत्ता से बाहर होते ही बघेल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और राम द्रोह के रास्ते पर चलते हुए अब पूजनीय संतों और राष्ट्र नायकों का अपमान करना उनकी नियति बन गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में भूपेश बघेल हाशिये पर चल रहे है इसी हताशा में सुर्खिया पाने बार बार अपना राजनीतिक स्तर दिखाते हुए घटिया बयान देते रहते हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठोकने ने कहा कि जहाँ एक ओर सरसंघचालक डॉ. भागवत संस्कृत के श्लोकों और भारतीय संस्कृति के संवर्धन के माध्यम से विश्व को शांति का संदेश दे रहे हैं, वहीं भूपेश बघेल जैसा 'निकम्मा' नेतृत्व केवल तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त है। डॉ. भागवत को श्लोक बोलते हुए चाहे जितने वीडियो भेजने की बात कहते हुए श्री ठोकने ने कहा कि राम-द्रोही राजनीतिक संस्कार की कुलजमा हैसियत रखने वाले बघेल ने एक खानदान की चाटुकारिता करने के अलावा किया क्या है? बघेल से सनातनी संस्कारों का पैरोकार होने की उम्मीद ही बेमानी है। श्री ठोकने ने कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह से मुस्लिम लीग की विचारधारा पर चल रही है। जिस पार्टी के नेता सनातन धर्म और उसके प्रतीकों का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। ठोकने ने कहा कि अपने इन्हीं ओछे बयानों के कारण बघेल अब सार्वजनिक जीवन में सम्मान का अधिकार खो चुके हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

यातायात नियमों से आमजनों को करें जागरूक: रामविचार

रायपुर। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत राजपुर के सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद, सांसद सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला पशु रोगी कल्याण समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम वर्चुअल रूप से जुड़े। इस दौरान सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, सामरी विधायक उद्देश्वरी पैंकरा, प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते,

जिला पंचायत अध्यक्ष हीरामुनी निकुंज, कलेक्टर राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर, वनमंडलाधिकारी आलोक वाजपेयी, जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर आर.एन. पाण्डेय, जनपद एवं नगरीय निकायों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री नेताम ने सांसद सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कहा कि शराब पीकर और तेज गति से वाहन चलाने वालों पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके। यातायात नियमों के संबंध में विस्तार से जानकारी देने के साथ-साथ लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने हाट-बाजारों में भी प्रचार-प्रसार कर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने सुझाव दिए।

कलेक्टर ने किया सेजबहार में मत्स्य पालन का अवलोकन

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह धरसींवा विकासखण्ड के दौरे पर निकले। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के हितग्राहियों द्वारा किए जा रहे मत्स्य पालन का निरीक्षण किया। वहां के हितग्राहियों ने बताया कि वहां के 05 नर्सरी एवं 04 तालाबों में मत्स्य पालन किया जा रहा है। नर्सरी में जो फिश सीड विकसित होते हैं उसे दुबारा तालाब में डाल दिया जाता है। इस प्रकार प्रति महीने करीब 17 टन का उत्पादन होता है। कलेक्टर ने हितग्राहियों से चर्चा करते हुए कहा कि इस योजना को अच्छी तरह से क्रियान्वयन करें, जल संरक्षण पर अधिक ध्यान देवें जिसके लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, एसडीएम श्री नंद कुमार चौबे, तहसीलदार श्री राकेश देवांगन, जनपद सीईओ धरसींवा श्री आशीष केशरवानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सहयोग केन्द्र के माध्यम से कार्यकर्ताओं के आवेदनों का हो रहा निराकरण

रायपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सहयोग केन्द्र में कार्यकर्ताओं के आवेदनों का लगातार निराकरण हो रहा है। गुरुवार को सहयोग केन्द्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कार्यकर्ताओं के कई आवेदनों का तत्काल निराकरण किया एवं अन्य आवेदनों को संबंधित विभागों में शीघ्र निराकरण करने के लिए भेजा। सहयोग केन्द्र में आज अलग-अलग जिलों से लगभग 50 से अधिक कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान सहयोग केन्द्र में प्रदेश मंत्री हर्षिता पांडेय एवं प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज मौजूद थे।

हजारों युवाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी में अवसर

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता एवं सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के कुल 5000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन शीघ्र ही जारी किया जा रहा है। शासन ने परीक्षा आयोजन के लिये छत्तीसगढ़ व्यापम को अधिकृत किया है एवं विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने संबंधी सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर आवश्यक प्रपत्र व्यापम को उपलब्ध करा दिया गया

है। इसके साथ ही सीधी भर्ती 2023 की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल शिक्षा विभाग में 5,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया फरवरी 2026 में शुरू करने जा रही है। इन पदों के लिए चयन व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, यह भर्ती राज्य के विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए की जा रही है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया के बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस आने वाले दिनों में जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के माध्यम से न केवल हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।

अतिरिक्त कक्ष का सांसद सोनी ने किया भूमिपूजन

रायपुर। पंडित भगवतीचरण शुक्ल वार्ड क्षेत्र स्थित शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय परिसर में 10 लाख रूपये की स्वीकृत लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्ष निर्माण का विधायक सुनील सोनी ने श्रीफल फोड़कर एवं कुदाल चलाकर कार्यारंभ किया। इस अवसर पर निगम सभापति सूर्यकांत राठौड, पंडित भगवतीचरण शुक्ल वार्ड पार्षद एवं नगर निगम संस्कृति विभाग अध्यक्ष अमर गिदवानी, नगर निगम जोन 4 जोन अध्यक्ष मुरली शर्मा, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. तपेशचंद्र गुप्ता, मंडल अध्यक्ष सुनील कुकरेजा,सामाजिक कार्यकर्ता पल्लवी पाण्डेय, अंकित निहाल, नगर निगम जोन 4 जोन कमिश्नर अरूण ध्रुव, कार्यपालन अभियंता शेखर सिंह, सहायक अभियंता दीपक देवांगन, उपअभियंता हिमांशु चंद्राकर, अंकिता अग्रवाल, शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के प्राध्यापको, विद्यार्थियों उपस्थित थे।

ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने पत्रकारों से साझा की विभागीय उपलब्धियां

प्रदेश को देश की ऊर्जा राजधानी बनाने की दिशा में प्रयास : डॉ. यादव

रायपुर। ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने आज नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ संवाद के ऑडिटोरियम में पत्रकारों के साथ ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा आने वाले वर्षों के लिए एक व्यापक कार्ययोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है।

डॉ. यादव ने जानकारी दी कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी, एनटीपीसी तथा निजी उत्पादकों को मिलाकर प्रदेश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 30 हजार 671.7 मेगावाट है। इसमें 28 हजार 824 मेगावाट ताप विद्युत, 220 मेगावाट जल विद्युत तथा सोलर, बायोमास आदि स्रोतों से 2,047 मेगावाट क्षमता शामिल है। ताप विद्युत क्षेत्र में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी की 2,840 मेगावाट, एनटीपीसी व निजी स्वामित्व के बिजलीघरों की 20 हजार 299 मेगावाट तथा कैप्टिव पॉवर प्लांट्स की 5 हजार 266 मेगावाट क्षमता है।

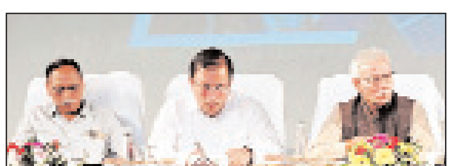

डॉ. यादव ने कहा कि भारत सरकार का फोकस ताप विद्युत पर निर्भरता कम कर कार्बन उत्सर्जन घटाने पर है। नेट जीरो कार्बन लक्ष्य के तहत वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे देश की 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय स्रोतों से पूरी की जा सके। इस दिशा में जल विद्युत एवं पंप स्टोरेज परियोजनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ग्रिड संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगी।

राज्य शासन द्वारा पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नीति 2023 लागू की गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी द्वारा 8,300 मेगावाट क्षमता के छह स्थलों का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें से पांच के फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और डीपीआर निर्माणाधीन है। निजी क्षेत्र में भी लगभग 5,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं पर कार्य जारी है।

ऊर्जा सचिव डॉ. यादव ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के तहत एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एवं राज्य उत्पादन कंपनी के संयुक्त उपक्रम द्वारा लगभग 2 हजार मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। इनमें अटल बिहारी ताप विद्युत गृह के जलाशय में 6 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर, कोरबा पूर्व के बंद राखड़ बांध पर 32 मेगावाट सौर संयंत्र तथा 500 मेगावाट-ऑवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना प्रस्तावित है। ऊर्जा सचिव ने बताया कि प्रदेश को देश की ऊर्जा राजधानी बनाने की दिशा में 32 हजार 100 मेगावाट क्षमता की नई परियोजनाओं हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ एमओयू किए गए हैं। इन परियोजनाओं में 12 हजार 100 मेगावाट ताप विद्युत, 4 हजार 200 मेगावाट न्यूक्लियर, 2 हजार 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर तथा 13 हजार 300 मेगावाट पंप स्टोरेज क्षमता शामिल है।

जनजातीय संग्रहालय फेस-2 का कार्य जल्द होगा प्रारंभ

रायपुर। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का आज प्रमुख सचिव सोनमणी बोरा ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा राज्य के नवा रायपुर में बेहतरीन डिजिटल संग्रहालय बनकर तैयार हुआ है। इनका रख-रखाव तथा रंगरोदन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने संग्रहालय को स्वच्छ और साफ-सुथरे रखने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि संग्रहालय का अवलोकन करने राज्य के विभिन्न जिलों, देश के अन्य राज्यों सहित विदेशों से भी पर्यटक आ रहे हैं। संग्रहालय के बनने से प्रदेश का मान सम्मान देश-दुनिया में बढ़ा है। श्री बोरा ने कहा कि विभाग के सभी

अधिकारी-कर्मचारी संकल्प ले कि महीने में कम से कम एक दिन संग्रहालय में श्रम दान करेंगें और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करेंगें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी श्रमदान करने आएंगे। प्रमुख सचिव बोरा ने कहा कि जनजातीय संग्रहालय फेस-2 निर्माण के लिए जल्द ही कार्य प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा।

इस दौरान आदिम जाति विकास विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर, छत्तीसगढ राज्य अंत्याव्यवसायी विकास निगम के संचालक डॉ. जगदीश सोनकर, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की संचालक हिना अनिमेष नेताम, सयुक्त सचिव बी. के. राजपूत, कार्यपालन अभियंता त्रिदिप चक्रवर्ती, रायपुर जिला के सहायक आयुक्त शरदचन्द्र शुक्ला सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स तथा आर्टिस्ट उपस्थित थे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष एक नवंबर को राज्योत्सव के अवसर पर पीएममोदी के कर कमलों से जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ हुआ था।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.